

## महिला आरक्षक की शिकायत के बाद डिप्टी कलेक्टर निलंबित

छ.ग.फ्रंटलाइन बीजापुर। एक महिला आरक्षक की शिकायत के बाद जिले में पदस्थ डिप्टी कलेक्टर दिलीप उडके को निलंबित कर दिया गया है। बालोद जिले के डौंडी थाना में दर्ज यह प्रकरण कुछ महीने पहले का है। महिला ने डिप्टी कलेक्टर उडके पर आरोप लगाया है कि उन्होंने शादी का वादा कर उससे कई बार शारीरिक संबंध बनाए, जबरन गर्भपात कराया और आर्थिक रूप से भी उसका शोषण किया।



जिला प्रशासन ने उडके को बचाने के लिए फर्जी प्रमाण पत्र जारी किए और नियमों के विपरीत अवकाश मंजूर किया। महिला ने अपने आरोपों के समर्थन में दस्तावेज भी प्रस्तुत किए हैं। शिकायत के मुताबिक, वर्ष 2017 में जब वह डौंडी के आईटीआई में पढ़ाई कर रही थी, तभी उसकी उडके से जान-पहचान हुई, जो बाद में प्रेम संबंध में बदल गई। महिला का कहना है कि उडके ने शादी का भरोसा देकर उससे संबंध बनाए। मार्च 2017 में गर्भवती होने पर उडके ने पढ़ाई और नौकरी का हवाला देकर शादी टाल दी और दवा देकर गर्भपात करा दिया।

महिला के अनुसार, अगस्त 2017 में उसकी पुलिस विभाग में नौकरी लगने के बाद भी वह उडके से शादी की उम्मीद में उसकी पढ़ाई और कोचिंग के लिए हर महीने 4 से 5 हजार रुपये भेजती रही। वर्ष 2020 में उडके पीएससी परीक्षा पास कर डिप्टी कलेक्टर बने और बीजापुर में पदस्थ हुए। इसके बाद भी शादी का आश्वासन देकर संबंध बनाए जाते रहे।

## गर्भवती होने पर जबरन गर्भपात कराने का आरोप

महिला ने आरोप लगाया कि जनवरी 2025 में वह बीजापुर स्थित सरकारी आवास में लगभग एक सप्ताह रही, जहां गर्भवती होने की जानकारी देने पर उडके ने उसे जबरन गर्भपात की दवा दी। फरवरी और मार्च 2025 में भी शादी का झांसा देकर संबंध बनाए गए। महिला ने बैंक से लोन लेकर कुल 3.30 लाख रुपये उडके के खाते में ट्रांसफर किए। 15 मई 2025 को तीसरी बार गर्भवती होने पर भी गर्भपात कराने का आरोप लगाया गया है। इसके अतिरिक्त महिला का कहना है कि फरवरी 2023 में उडके ने उसके नाम पर एते मॉडकल कार खरीदी, जिसे फरवरी 2024 में उसके खाते में रकम डालकर अपने नाम ट्रांसफर कर लिया। महिला की शिकायत पर डौंडी थाना में एफआईआर दर्ज की गई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए बीजापुर प्रशासन ने डिप्टी कलेक्टर दिलीप उडके को निलंबित कर दिया है और आगे की जांच जारी है।

बाद भी शादी का आश्वासन देकर संबंध बनाए जाते रहे।

## सरगुजा के 4 गांवों को आईएमए सरगुजा ने लिया गोद

हर तीन महीने में लगेगा स्वास्थ्य शिविर, हर सुविधा होगी उपलब्ध

छ.ग.फ्रंटलाइन अम्बिकापुर। सरगुजा जिले में ग्रामीण स्वास्थ्य को मजबूत बनाने की दिशा में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) सरगुजा ने एक प्रेरणादायी और जनहितकारी पहल करते हुए बिनिया, पटकोरा, लब्जी (मैनपाट) एवं डंडकेसर गांवों को गोद लिया है। इस पहल का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि इन गांवों के नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भटकना न पड़े, बल्कि उन्हें नियमित, भरोसेमंद और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधा उनके क्षेत्र में ही उपलब्ध हो सके। आईएमए सरगुजा द्वारा इन गांवों के लिए स्वास्थ्य संबंधी



हर आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। इस अभियान के अंतर्गत हर तीसरे महीने एक गांव में नि:शुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसमें स्वास्थ्य जांच, चिकित्सकीय परामर्श, आवश्यक उपचार, स्वास्थ्य जागरूकता एवं जरूरत अनुसार आगे की चिकित्सा सुविधा से जोड़ने की व्यवस्था की जाएगी। आईएमए सरगुजा के

सचिव डॉ. अर्पण सिंह चौहान ने बताया कि, आईएमए का प्रयास है कि स्वास्थ्य सेवा केवल शहरों तक सीमित न रहे। ग्रामीण अंचलों तक नियमित स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाना हमारा सामाजिक दायित्व है। यह पहल निरंतर जारी रहेगी और जरूरत अनुसार इसका विस्तार भी किया जाएगा। आईएमए सरगुजा की यह पहल समाज के प्रति डॉक्टरों की संवेदनशीलता, जिम्मेदारी और सेवा भावना का सशक्त उदाहरण है। यह अभियान निश्चित रूप से अन्य संस्थाओं एवं समाज के सभी वर्गों को भी जनहित में आगे आने की प्रेरणा देगा।

## सत्यापन समिति ने आपत्ति को खारिज किया, सुनवाई की तिथि फिर बढ़ी

मामला प्रतापपुर विधायक के कथित जाति प्रमाणपत्र प्रकरण से जुड़ा

छ.ग.फ्रंटलाइन बलरामपुर। प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र की भाजपा विधायक शकुंतला सिंह पोते पर लगी अटकलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। विधायक के कथित फर्जी जाति प्रकरण पर गुरुवार को जिला स्तरीय सत्यापन समिति के समक्ष सुनवाई हुई। इसमें विधायक की ओर से सत्यापन समिति के सुनवाई के क्षेत्राधिकार को लेकर आपत्ति की, इसे सत्यापन समिति ने खारिज कर दिया, अब मामले में 17 मार्च को सुनवाई होगी। इस दौरान विधायक शकुंतला पोते को जाति प्रमाण पत्र से संबंधित दस्तावेज समिति के समक्ष पेश करने होंगे।



समाज के अतिवासी समाज के धन सिंह धुर्वे ने हाईकोर्ट में विधायक के जाति प्रमाण पत्र के संबंध में याचिका लगाया है। हाईकोर्ट के निर्देश पर जिला स्तरीय सत्यापन समिति में हो रही जाति प्रकरण की सुनवाई में विधायक पक्ष के अधिवक्ताओं ने तर्क रखा था कि पिछली सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों में बहस हुई थी और विधायक के अधिवक्ताओं ने आपत्ति दर्ज कराई थी। सत्यापन समिति ने विधायक पक्ष की आपत्ति को खारिज करते हुए सुनवाई के लिए 17 मार्च की तिथि निर्धारित कर दी है।

आदिवासी समाज के अधिवक्ताओं का तर्क है कि उन्होंने विधायक की विधायकी को लेकर याचिका दायर नहीं की है, जाति प्रमाण पत्र के संबंध में याचिका लगाई है। सत्यापन समिति जाति प्रमाण पत्र के संबंध में ही सुनवाई कर रही है। फिलहाल प्रकरण की सुनवाई ने एक बार फिर सियासी फिजा में जाति प्रमाण पत्र शून्य घोषित करने जैसी अनौपचारिक परिस्थितियां खड़ी कर दी है। जैसे-जैसे सुनवाई की तारीखों का ऐलान होता है, वैसे ही लोगों में प्रकरण का नतीजा जानने की ललक पैदा हो जाती है। इस बार भी हर बार की तरह तारीख बढ़ा दी गई है। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि अगली सुनवाई में दोनों पक्ष अधिवक्ता क्या नया तर्क रखते हैं।

## बोलरो और पिकअप की ठोकर से घायल 2 युवकों की मौत

छ.ग.फ्रंटलाइन अम्बिकापुर। बोलरो और पिकअप की ठोकर से घायल दो युवकों की इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने मामले में मर्ग कायम कर लिया है।

जानकारी के मुताबिक एमसीबी जिला के इगाराखंड का ब्रिजेश सिंह पिता रन सिंह गोड 27 वर्ष का ससुराल केल्लारी थाना क्षेत्र के ग्राम चरवाही में है। युवक अपने ससुराल वैवाहिक आयोजन में शामिल होने के लिए गया था। बुधवार को वह गांव में ही घूम रहा था, इसी दौरान बोलरो वाहन क्रमांक सीजी 16 बी 1616 का चालक ठोकर मार दिया। घायल युवक को केल्लारी स्वास्थ्य लेजर स्क्वज पहुंचे, यहां से रिफर करने पर मनेन्द्रगढ़ जिला अस्पताल से होते मेडिकल कॉलेज अस्पताल अम्बिकापुर पहुंचे, यहां इलाज के दौरान युवक की बुधवार को शाम करीब 7 बजे मौत हो गई।

## वन विभाग के शासकीय आवास से चंदन का पेड़ काटकर ले गए तस्कर

सेवानिवृत्त वन विभाग के दरोगा सुबह उठे तो पेड़ का मुख्य हिस्सा था गायब

एसडीओ के हर्बल हाउस के बाद वन परिसर के आवास को बनाया निशाना



छ.ग.फ्रंटलाइन अम्बिकापुर। कलेक्टर बंगला रोड में स्थित हर्बल हाउस से चंदन का पेड़ काटकर ले जाने के मामले की आंच ठंडी नहीं पड़ी थी, पुनः वन विभाग के एक सेवानिवृत्त कर्मचारी के शासकीय आवास की बाड़ी में लगे चंदन के पेड़ का तना काटकर चोर ले गए। हेरत की बात यह है कि वन विभाग के अधिकारी-कर्मचारियों के आवास, कार्यालय के आसपास तस्कर चंदन का पेड़ बेखौफ काटकर ले जा रहे हैं, इसकी भनक वन अमले को नहीं लग पा रही है, और तस्कर अपने मसूबे में सफल नहीं हो रहे हैं। ऐसे में जंगलों की सुरक्षा को लेकर वन अमला कितना सजग रहता होगा, इसकी कल्पना की जा सकती है।

जानकारी के मुताबिक 18-19 फरवरी की दरम्यानी रात करीब दो बजे लुण्ड्रा वन परिक्षेत्र में उप वन परिक्षेत्राधिकारी के पद से हाल में सेवानिवृत्त हुए एन.डी. वर्मा के शासकीय आवास की बाड़ी में लगे चंदन के पेड़ को काटकर तस्कर ले गए। एक दिन के अंतराल में चंदन के पेड़ काटकर ले जाने की दूसरी घटना सामने आई है। तस्करों ने पहले कलेक्टर बंगला रोड में महिला थाना के सामने रहने वाले एसडीओ के हर्बल हाउस को निशाना बनाया, अब इससे लगे वन विभाग के कॉलोनी में रहने वाले सेवानिवृत्त उप वन परिक्षेत्राधिकारी के शासकीय आवास की बाड़ी में चुसकर चंदन का पेड़ काटकर ले जाने की हिमाकत कर बैठे। एन.डी. वर्मा ने बताया कि दौरे के बीच वे वर्ष 2000 में मनेन्द्रगढ़ के गेज नर्सरी से बेल और चंदन का पेड़ लाकर अपने शासकीय निवास में स्थित बाड़ी में लगाए थे। बेल का पेड़ तो सूख गया,

## तस्करों की सक्रियता और विभागीय सुस्ती सवालियों के घरे में

लगातार चंदन के पेड़ों को काटकर ले जाने की घटनाएं सामने आने के बाद भी वन विभाग की सुस्ती समझ से परे है। वन परिसर और आसपास से चोरी की ये तीसरी घटना है। 16-17 फरवरी की दरम्यानी रात को ही हर्बल हाउस से चंदन का विशाल पेड़ काटकर ले जाने का मामला प्रकाश में आया था, जो वन विभाग के एसडीओ का निवास है। एक दिन के अंतराल में पुनः वन परिसर के बीच में स्थित कर्मचारी आवास के बाड़ी से चंदन का पेड़ काटकर ले जाने का मामला न सिर्फ हैरान करने वाला है, बल्कि वन विभाग के आला अफसरों के नाक के नीचे हो रही घटनाओं को सवालियों के घरे में ले रहा है। चोरों के द्वारा चंदन के पेड़ को काटने में आरा मशीन का उपयोग किया जा रहा है। इधर वन विभाग बेशकीमती चंदन के पेड़ों की सुरक्षा के लिए कोई ठोस कदम उठाने में नाकाम साबित हो रहा है। दिसंबर 2024 में तस्करों ने मुख्य वन संरक्षक कार्यालय के पीछे स्थित नर्सरी से तीन चंदन के पेड़ों को काटकर पार कर दिया था। माखन विहार फॉर्म हाउस से भी ढाई दशक पुराने लाखों के चंदन के चार पेड़ों की चोरी हुई थी। सभी घटनाएं रात्रि पहर में हुईं, लेकिन तस्करों का पता नहीं चला। देखना यह है कि लगातार हो रही इन घटनाओं के बाद अपनी जिम्मेदारियों पर परदा डालने की कोशिश करने वाला वन अमला क्या कदम उठाता है।

लेकिन 26 वर्ष में चंदन का पेड़ अच्छा बड़ा और छायादार आकार ले चुका था, इसका 10 मीटर से अधिक मुख्य तना को काटकर तस्कर बीती रात ले गए। बाड़ी और निवास में बीच अधिक फासला होने के कारण इसकी भनक उन्हें नहीं लग पाई। सुबह उठे तो चंदन के पेड़ का कटा हुआ कुछ हिस्सा जमीन में पड़ा था और कीमती हिस्सा गायब था। इसकी सूचना उन्होंने तत्काल वन परिक्षेत्राधिकारी अम्बिकापुर को दी थी, इसके बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचे और चंदन के पेड़ का कटा अवशेष जब्त करके ले गई है।

## 896 नग नशीले कैप्सूल को खपाने के पहले 03 गिरफ्तार

संभागीय आबकारी उड़नदस्ता ने की कार्रवाई

छ.ग.फ्रंटलाइन अम्बिकापुर। संभागीय आबकारी उड़नदस्ता सरगुजा की टीम ने प्रतिबंधित नशीले कैप्सूल के साथ तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से 896 नग कैप्सूल जब्त करने में टीम सफल हुई, तीनों आरोपियों को जेल दाखिल कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक 18 फरवरी को संभागीय आबकारी उड़नदस्ता टीम, सहायक जिला आबकारी अधिकारी रंजीत गुप्ता के नेतृत्व में दरिमा थाना क्षेत्र के कतकालो बाजार पहुंची थी। यहां एक संदिग्ध मोटरसाइकिल सवार को देखकर टीम ने रोकने का प्रयास किया लेकिन वह भागने लगा, जिसे पीछा करके पकड़ने में आबकारी अमला सफल हुआ। पूछताछ करने पर वह अपना नाम मुकेश गुप्ता निवासी करजी थाना दरिमा का होना बताया। तलाशी लेने पर उसके पास रखे झोले से 224 नग स्पैसमो प्राक्सोवीन प्लस नशीला कैप्सूल मिला, जिसे टीम ने बरामद किया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इसी क्रम में टीम को 18 फरवरी की शाम को मुखबिर से पुनः सूचना मिली कि बतौली थाना क्षेत्र के सुआरपारा में पानी टंकी के पास दो लड़के नशीले कैप्सूल का सप्लाई करने वाले हैं। सहायक जिला आबकारी अधिकारी अपनी टीम ने घेराबंदी करके दोनों लड़कों राहुल तिग्गा एवं नितेश चौहान निवासी ग्राम बिरिमकेला को पकड़ा। इनके कब्जे से 472 नग स्पैसमो प्राक्सोवीन प्लस कैप्सूल जब्त किया गया। आरोपियों को एनडीपीएस एक्ट की धारा 22सी के तहत गिरफ्तार किया गया। 19 फरवरी को तीनों आरोपियों को विशेष न्यायालय अम्बिकापुर में रिमांड हेतु पेश किया गया, जहां से जेल दाखिल का आदेश प्राप्त हुआ। कार्रवाई में सहायक जिला आबकारी अधिकारी के साथ मुख्य आरक्षक रमेश दुबे, कुमार राम, अशोक सोनी, नगर सैनिक गणेश पांडे,



ओमप्रकाश गुप्ता, महिला सैनिक चंद्रावती की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

## डिहरीऑनसान से लाते थे नशीला कैप्सूल, पहली बार पकड़ में आए

सहायक जिला आबकारी अधिकारी रंजीत गुप्ता ने बताया सरगुजा को नशा मुक्त करने की दिशा में लगातार प्रयास जारी है। इसके पहले उन्होंने टीम के साथ कई बड़ी कार्रवाई करते हुए नशीले इंजेक्शन की छोटी-बड़ी खेप को बरामद किया था। अंतर्राज्यीय मदिरा की बड़ी खेप पकड़ने में भी टीम को सफलता मिली थी। इस बार नशे के प्रयोग में लाए जाने वाले कैप्सूल के साथ आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। आरोपी झारखंड के डिहरीऑनसान से नशीले कैप्सूल की खेप लेकर आते थे, और बिक्री करते थे। जब्त किए गए नशीले कैप्सूल की कीमत 50 हजार रुपये हैं, जिसे नशीले कैप्सूल के साथ आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। आरोपी झारखंड के डिहरीऑनसान से नशीले कैप्सूल की खेप लेकर आते थे, और बिक्री करते थे। जब्त किए गए नशीले कैप्सूल की कीमत 50 हजार रुपये हैं, जिसे नशीले कैप्सूल के साथ आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है।

## महापौर ने यूपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण छात्र को सौंपा एक लाख रुपये का चेक

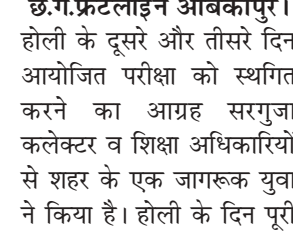
मेधावी छात्रों को महापौर सम्मान निधि से प्रोत्साहन राशि देने का लिया था निर्णय



छ.ग.फ्रंटलाइन अम्बिकापुर। नगर पालिक निगम अम्बिकापुर के महापौर कक्ष में महापौर मंजूषा भगत एवं सभापति हरमिंदर सिंह टिन्नी ने महापौर सम्मान निधि से संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा उत्तीर्ण कर शहर को गौरवान्वित करने वाले मेधावी छात्र को एक लाख रुपये का चेक सौंपा। केशव गर्ग पिता विनोद गर्ग शहर के चंदगीराम टॉवर, अग्रसेन वार्ड के निवासी हैं। इनका उत्साहवर्धन करते हुए उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दी गईं। महापौर मंजूषा भगत ने निर्णय लिया था कि, शहर के ऐसे मेधावी विद्यार्थी जो संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की परीक्षा उत्तीर्ण कर शहर को गौरव प्रदान करेंगे, उन्हें महापौर सम्मान निधि से एक लाख की राशि भेंट कर प्रोत्साहित किया जाएगा। इसका उद्देश्य अन्य युवा भी देश के सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा में सफल होकर नगर एवं प्रदेश को गौरव प्रदान करना है। योजनांतर्गत पूर्व में भी नगर की मेधावी छात्रा प्राची जायसवाल पिता मोहन जायसवाल निवासी बौरिपारा एवं छात्र नीरज कुमार गोयल पिता विजय गोयल निवासी कुडला सिटी, खरसिया रोड को भी एक-एक लाख रुपये भेंट करके प्रोत्साहित किया जा चुका है। इस अवसर पर महापौर परिसर के सदस्य मनोप सिंह, जितेंद्र सोनी, ममता तिवारी, श्वेता गुप्ता, प्रियंका गुप्ता, विपिन पांडेय, शशिकांत जायसवाल, सुरात घोष, पार्षद मनोज गुप्ता, विकास पांडेय, परमिंदर सिंह, सचिव सरिता गुप्ता सहित अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे।

## होली पर्व के दूसरे दिन परीक्षा, पुलिस और निगम परिवार की कैसे मनेगी होली

कलेक्टर से घोषित परीक्षाओं को आगामी दो दिन आगे के लिए बढ़ाने का आग्रह किया



छ.ग.फ्रंटलाइन अम्बिकापुर। होली के दूसरे और तीसरे दिन आयोजित परीक्षा को स्थगित करने का आग्रह सरगुजा कलेक्टर व शिक्षा अधिकारियों से शहर के एक जागरूक युवा ने किया है। होली के दिन पूरी तन्मयता से सेवा देने वाले पुलिस, नगर निगम सहित कई जिम्मेदार अधिकारी-कर्मचारी अगले दिन अपने परिवार और सहपाठियों के साथ होली पर्व मनाते हैं। होली के दूसरे दिन से ही परीक्षाएं आयोजित किए जाने से इनकी खुशियों का रंग फीका पड़ जाएगा। बता दें कि रांगों का पर्व होली 4 मार्च को हर्षोल्लास मनाया जाएगा। हाल में स्कूली परीक्षाओं के कारण होली का पर्व बच्चों के लिए मस्ती भरा भले ही न हो, लेकिन इस दिन वे पढ़ाई के साथ परिवार के सदस्यों के साथ उल्लास और



उमंग के साथ पर्व मनाएंगे। ऐसे में होली पर्व के दूसरे ही दिन 5 मार्च को परीक्षा का आयोजन करना बच्चों की भावनाओं पर अनावश्यक दबाव डालने जैसा होगा। शहर के जागरूक युवा शिवेश सिंह बाबू ने इसे अनुचित करार देते हुए कलेक्टर सरगुजा का ध्यानकर्षण कराया है, और कहा है कि होली के दूसरे दिन पुलिस प्रशासन, नगर निगम के स्वच्छता एवं जल प्रदाय शाखा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी-कर्मचारियों को भी होली पर्व मनाने का मौका मिलना चाहिए,

जो एक स्वाभाविक और सामाजिक प्रक्रिया है। इनके बच्चे भी पारिवारिक रूप से इस उत्सव में शामिल होते हैं। ऐसे में होली के ठीक बाद 5 व 6 मार्च को परीक्षा आयोजित करना स्कूली बच्चों और उनके परिजनों के लिए असुविधाजनक होगा। आग्रह किया गया है कि बच्चों के भविष्य के साथ उनके व परिवार के त्योहारी उल्लास भरी भावनाओं का सम्मान करते हुए परीक्षा की तिथि को आगे बढ़ाने शैक्षणिक संस्थाओं को आदेशित किया जाए, जिससे होली पर्व का उमंग और उल्लास विद्यार्थियों के बीच बरकरार रहे। उल्लेखनीय है कि शहर के कुछ नामचीन निजी स्कूल भी होली पर्व के ठीक दूसरे दिन परीक्षा की तिथि निर्धारित करके रखे हैं, जिससे बच्चे मायूस हैं, वहीं अभिभावक भी इसे उचित नहीं मान रहे हैं।

# पीएम जनमन की सड़कों का मापदंडों के अनुरूप हो निर्माण : सांसद

★ यातायात नियमों के प्रति आमजनों को करें जागरूक : नेताम

★ जिला खनिज न्यास, सांसद सड़क सुरक्षा एवं पशु रोगी कल्याण समिति की बैठक सम्पन्न

बलरामपुर, छ.ग. फ्रंटलाइन। जनपद पंचायत राजपुर के सभाकक्ष में जिला खनिज संस्थान न्यास की शासी परिषद, सांसद सड़क सुरक्षा समिति एवं जिला पशु रोगी कल्याण समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में प्रदेश के आदिम जाति विकास, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री रामविचार नेताम वरुचुअल रूप से जुड़े। इस दौरान सरगुजा सांसद श्री चिंतामणि महाराज, सामरी विधायक श्रीमती उदेश्वरी पैकरा, प्रतापपुर विधायक श्रीमती शकुंतला पोते, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती हीरामुनी निकुंज, कलेक्टर श्री राजेंद्र कटारा, पुलिस अधीक्षक श्री वैभव बैंकर, वनमंडलाधिकारी श्री आलोक वाजपेयी, जिला पंचायत सीईओ श्रीमती नयनतारा सिंह तोमर, अपर कलेक्टर श्री आर.एन. पाण्डेय, जनपद एवं नगरीय निकायों के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

**जिला खनिज संस्थान न्यास के कार्यों की समीक्षा**

जिला खनिज संस्थान न्यास के अंतर्गत निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए मंत्री श्री रामविचार नेताम ने आवश्यक निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने पिछले वर्ष स्वीकृत कार्यों में से पूर्ण हो चुके कार्यों की भी जानकारी ली। बैठक में जिला पंचायत सीईओ श्रीमती नयनतारा सिंह तोमर ने वित्तीय

वर्ष 2024-25 के महत्वपूर्ण कार्यों एवं आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 की कार्ययोजना के



अनुमोदन तथा गतिविधियों की विस्तृत जानकारी दी। जिला पंचायत सीईओ श्रीमती तोमर ने डीएमएफ मद के अंतर्गत प्राप्त राशि एवं व्यय, कार्यों की प्रगति और महत्वपूर्ण कार्यों की जानकारी प्रस्तुत की।

**हेलमेट एवं सीट बेल्ट की उपयोगिता के साथ यातायात नियमों के पालन के निर्देश** सांसद सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में मंत्री श्री नेताम ने शराब पीकर और तेज गति से वाहन चलाने वालों पर चालानी कार्रवाई करने के सख्त निर्देश दिए, जिससे सड़क दुर्घटनाओं पर नियंत्रण किया जा सके।

उन्होंने कहा कि यातायात नियमों के संबंध में विस्तार से जानकारी देने के साथ-साथ

कार्यों में तेजी लाने को कहा। उन्होंने नाली निर्माण और पानी निकासी की उचित व्यवस्था के

लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है। उन्होंने हाट-बाजारों में भी प्रचार-प्रसार कर लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के निर्देश दिए। उन्होंने सड़क दुर्घटना से बचने के लिए अनिवार्य रूप से हेलमेट एवं चार पहिया वाहनों में सीट बेल्ट की उपयोगिता सुनिश्चित करने को कहा। सांसद श्री महाराज ने जिले में सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए एक प्रभावी कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने सड़क सुरक्षा के संबंध में जनजागरूकता लाने और राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण

लिए भी आवश्यक निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारी को यह सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए कहा कि सभी वाहन चालक आवश्यक दस्तावेजों के साथ यातायात नियमों का पालन करते हुए वाहन चलाए। उन्होंने लोगों को यह जागरूक करने को कहा कि वे नषे में वाहन का उपयोग न करें। ताकि आकस्मिक परिस्थितियों में दुर्घटना होने पर बीमा का लाभ मिल सके। सांसद ने पीएम जनमन योजना के अंतर्गत निर्माणधीन सड़कों को निर्धारित मापदंडों के अनुरूप बनाने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की शिथिलता ना बरती जाए। पुलिस अधीक्षक श्री वैभव बैंकर ने आगामी कार्ययोजना के बारे में अवगत कराते हुए जानकारी दी कि योजनाबद्ध तरीके से अंतर्राज्यीय चेक पोस्ट और दुर्घटना जन्य क्षेत्रों में सीसीटीवी के माध्यम से सतत निगरानी रखी जाएगी।

**जिला पशु रोगी कल्याण समिति की बैठक** जिला पशु रोगी कल्याण समिति की बैठक में उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं ने अब तक हुए कार्यों एवं प्रस्तावित कार्यों की विस्तृत जानकारी दी। इस दौरान पंजीयन शुल्क के निर्धारण, आवश्यक संसाधनों के ऋय और विभागीय कार्यों के लिए तकनीकी मशीनों की खरीदी के संबंध में चर्चा कर इनके अनुमोदन हेतु प्रस्ताव रखे गए।

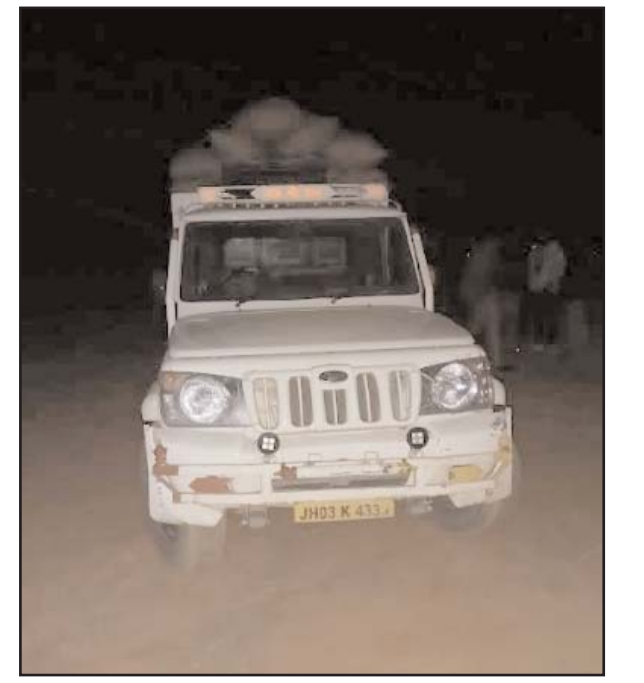
## मानी धान खरीदी केंद्र में गड़बड़ी की कोशिश नाकाम, 75 बोरी धान सहित दो पिकअप वाहन जब्त

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन बिश्रामपुर। ग्राम पंचायत मानी में स्थित धान खरीदी केंद्र में अनियमितताओं को छिपाने के उद्देश्य से समिति के कर्मचारियों द्वारा अवैध तरीके से धान खपाने की कोशिश का मामला उजागर हुआ है। गौरतलब है कि मंगलवार की रात करीब 11 बजे दो पिकअप वाहन धान से लदे हुए खरीदी केंद्र परिसर में पहुंचे। बताया जा रहा है कि यह धान रिकॉर्ड में दर्ज नहीं था और इसे पूर्व में हुई गड़बड़ियों को समायोजित करने के लिए केंद्र में खपाने की तैयारी की जा रही थी।

स्थानीय ग्रामीणों को देर रात केंद्र परिसर में ही रही हलचल पर संदेह हुआ। जब ग्रामीण मौके पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि दो पिकअप वाहन से धान उतारने की तैयारी चल रही है। ग्रामीणों ने तत्काल वाहन चालकों और मौजूद कर्मचारियों से पूछताछ की, लेकिन स्पष्ट जवाब नहीं मिलने पर उन्होंने वाहनों को रोक लिया और प्रशासन को सूचना दी। सूचना मिलते ही संबंधित प्रशासनिक अधिकारी और खाद्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची। प्रारंभिक जांच में धान से संबंधित आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जा सके।

संदेह के आधार पर दोनों पिकअप वाहन में लाए गए धान को जब्त कर लिया गया है। खाद्य विभाग ने धान को अपने कब्जे में लेकर पंचनामा तैयार

किसके निर्देश पर उसे केंद्र में खपाने की कोशिश की गई। घटना के बाद ग्रामीणों ने निष्पक्ष जांच की मांग की है। जिला खाद्य अधिकारी संदीप भगत ने



किया और आगे की वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि पूरे मामले की विस्तृत जांच की जाएगी। खरीदी केंद्र के रिकॉर्ड, स्टॉक रजिस्टर और परिवहन दस्तावेजों की जांच कराई जाएगी ताकि यह स्पष्ट हो सके कि धान कहाँ से लाया गया और

बताया कि दो पिकअप वाहन की जल्दी की गई है। जिसमें एक पिकअप वाहन में 75 बोरी धान लोड था। जानकारी मिला है कि दूसरी पिकअप की धान खाली हो चुका था। अभी जांच चल रही है, जिससे जांच उपरांत संबंधित दोषियों के खिलाफ उचित की जाएगी।

## सड़क पर केक काटा, फंसी रही एम्बुलेंस वायरल वीडियो मामले में जुर्म दर्ज

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन बिश्रामपुर। बनारस हाइवे मार्ग पर आधा दर्जन युवकों द्वारा जन्मदिन मनाने का मामला वायरल वीडियो में सामने आया है। वायरल वीडियो के आधार पर लटोरी पुलिस ने अंबिकापुर निवासी अंशुल अग्रवाल एवं अमितेश गुप्ता सहित आधा दर्जन युवकों के खिलाफ धारा 285, 126 (2) के तहत जुर्म दर्ज कर मामले की जांच शुरू

की है। घटना 16 फरवरी के देर शाम ग्राम पंचायत सोनवाही के नारायणपुर बस्ती आरव रेस्टोरेंट के सामने की बताई गई है। बताया जा रहा है कि युवकों ने जन्मदिन मनाने की सड़क में कार खड़ी कर कार के बोनट पर केक काटा और जमकर आतिशबाजी के साथ हल्ला मचाया, जिससे स्टेड हाइवे में करीब बीस मिनट तक जाम की

स्थिति निर्मित हो गई थी। इस दौरान अंतरराज्यीय मार्ग में

होने के बाद पुलिस ने जुर्म दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि युवकों के इस कारनामे के कारण उत्पन्न सड़क जाम में एंबुलेंस बीस मिनट तक फंसी रही। सूरजपुर एसडीओपी अभिषेक पैकरा ने बताया कि पुलिस ने दो नामजद सहित आधा दर्जन युवकों के खिलाफ जुर्म दर्ज कर आरोपियों की पतासाजी में जुटी है।



## धान चोरी में पिता ने दर्ज कराई रिपोर्ट, जांच में बेटे समेत दो गिरफ्तार

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन बिश्रामपुर। ग्राम पंचायत कुमदा बस्ती में धान चोरी की वारदात में शामिल प्रार्थी के पुत्र समेत एक अन्य युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय पेश कर दिया है। बिश्रामपुर पुलिस ने बताया कि ग्राम पंचायत कुमदा बस्ती निवासी 60 वर्षीय प्रार्थी रामविलास राजवाड़े ने थाना बिश्रामपुर पहुंचकर अपने घर से धान चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने मामले में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ धारा 331(4), 305(ए), 112 (2) और 3(5) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर जांच शुरू की। धान की चोरी की तलाश में जुटी पुलिस को मुखबिर से अहम सूचना मिली। सूचना के आधार पर टीम ने कार्रवाई करते हुए घेराबंदी कर दो युवकों को हिरासत में लिया। पूछताछ के दौरान जब सख्ती दिखाई गई तो दोनों ने चोरी की घटना स्वीकार कर ली। हैरानी की बात यह रही कि आरोपियों में एक नाम खुद शिकायतकर्ता के बेटे का था। पुलिस ने मामले में आरोपी 22 वर्षीय मुन्ना

पैकरा पिता इंदरू निवासी फोकटपारा शिवनंदनपुर के अलावा प्रार्थी के पुत्र 30 वर्षीय



दिगंबर राजवाड़े को गिरफ्तार कर आरोपियों की निशानदेही पर चोरी किए गए आठ बोरा धान, पल्सर मोटरसाइकिल व सबल को जब्त कर लिया है। आरोपियों को पुलिस ने रिमांड पर न्यायालय पेश कर दिया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आरोपी दिगंबर राजवाड़े नशेड़ी

किस्म का युवक है, जो नशे की लत की पूर्ति हेतु अपने साथी मुन्ना पैकरा के साथ मिलकर

खुद के घर में ही चोरी की घटना को अंजाम दिलाया था। आरोपियों ने पहले घर की गतिविधियों पर नजर रखी और मौका पाकर धान की बोरियां निकाल लीं। वारदात को अंजाम देने के लिए पल्सर मोटरसाइकिल का इस्तेमाल किया गया था।

## माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा आयोजित बोर्ड की परीक्षाएं आज से होगी प्रारंभ

बलरामपुर, छ.ग. फ्रंटलाइन। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा आयोजित हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा 20 फरवरी से प्रारंभ होगा और यह परीक्षा 18 मार्च 2026 तक चलेगी। इसी प्रकार हाईस्कूल मुख्य परीक्षा 21 फरवरी से 13 मार्च 2026 तक होगी। इन परीक्षाओं के लिए प्रातः 09 बजे से दोपहर 12.15 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा आयोजित बोर्ड परीक्षाओं के लिए जिले में 59 शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों को परीक्षा केन्द्र बनाया गया है, जहां 10वीं के 9235 एवं 12वीं के 6922 कुल 16 हजार 157 परीक्षार्थी शामिल होंगे। कलेक्टर श्री राजेंद्र कटारा के मार्गदर्शन में परीक्षा के दौरान परीक्षा केन्द्रों में सतत निगरानी, निरीक्षण एवं अनुचित साधनों के उपयोग को रोकने हेतु जिला एवं विकासखण्ड स्तरीय निरीक्षण दल का गठन भी किया गया है। जो सतत रूप से परीक्षा केन्द्रों का निरीक्षण करेंगे।

## जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति ( दिशा ) की बैठक सम्पन्न

केंद्र प्रायोजित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा कर समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण करने के निर्देश



बलरामपुर, छ.ग. फ्रंटलाइन। जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक राजपुर जनपद के सभाकक्ष में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता सरगुजा सांसद श्री चिंतामणि महाराज ने की। बैठक में जिले में संचालित केंद्र प्रायोजित योजनाओं की प्रगति, उनके क्रियान्वयन की स्थिति एवं जनकल्याणकारी कार्यक्रमों की व्यापक समीक्षा की गई। सांसद श्री महाराज ने विभागीय अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत प्रगति प्रतिवेदनों पर विस्तार से चर्चा करते हुए कहा कि विकास कार्यों को गुणवत्ता, पारदर्शिता और समयबद्धता के साथ पूरा किया जाना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की लापरवाही या देरी स्वीकार्य नहीं की जाएगी। बैठक में सामरी विधायक श्रीमती उदेश्वरी पैकरा, प्रतापपुर विधायक श्रीमती शकुन्तला पोते, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती हीरामुनी निकुंज, कलेक्टर श्री राजेंद्र कटारा, पुलिस अधीक्षक श्री वैभव बैंकर,

वनमंडलाधिकारी श्री आलोक वाजपेयी, जिला पंचायत सीईओ श्रीमती नयनतारा सिंह तोमर, अपर कलेक्टर श्री आर.एन. पाण्डेय, समिति के सदस्य एवं जनप्रतिनिधिगण सहित विभागीय अधिकारीगण उपस्थित रहे।

बैठक में सांसद श्री महाराज ने स्थानीय बोली में संबोधित करते हुए कहा कि हम सभी का मुख्य उद्देश्य यह होना चाहिए कि अधिक से अधिक नागरिकों तक केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं पहुंचाई जाएं, ताकि उन्हें अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों को गुणवत्ता, पारदर्शिता और समयबद्धता के साथ पूरा किया जाना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की लापरवाही या देरी स्वीकार्य नहीं की जाएगी। बैठक में सामरी विधायक श्रीमती उदेश्वरी पैकरा, प्रतापपुर विधायक श्रीमती शकुन्तला पोते, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती हीरामुनी निकुंज, कलेक्टर श्री राजेंद्र कटारा, पुलिस अधीक्षक श्री वैभव बैंकर,

त्वरित संज्ञान लेते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश भी दिए।

बैठक में श्री महाराज ने ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण केंद्र की योजनाओं का ध्यतल स्तर पर व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए। उन्होंने पीएम जनमन अंतर्गत सभी सूचकांकों की गहन समीक्षा करते हुए निर्धारित समयावधि में शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। मनरेगा, आजीविका गतिविधि, जल संवर्धन और प्रधानमंत्री आवास योजना की जानकारी लेते हुए उन्होंने इन कार्यों को समय से पूर्ण करने को कहा। कृषि विभाग की समीक्षा करते हुए उन्होंने रबी फसल के लिए खाद, बीज की उपलब्धता के साथ तिलहनी फसलों को बढ़ावा देने के निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित अधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि किसानों तक योजनाओं की जानकारी पहुंचाएँ, ताकि वे इनका लाभ ले सकें। इस दौरान उन्होंने श्रीविधि का उपयोग कर खेती करने पर भी जोर दिया। उन्होंने पीएम किसान सम्मान निधि

जोना के अंतर्गत पंजीयन कर अधिक से अधिक किसानों को लाभान्वित करने के निर्देश भी दिए।

स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा करते हुए उन्होंने जिले के अंतिम एवं दूरस्थ क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार की बात कही। इस दौरान सिकलसेल और टीबी का समुचित उपचार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने सभी स्वास्थ्य केंद्रों में चिकित्सकों की उपस्थिति की सतत मॉनिटरिंग करने को कहा। बैठक में जल संवर्धन, जल जीवन मिशन और पीएम उज्वला योजना के कार्यों की जानकारी लेते हुए लक्ष्य के अनुरूप प्रगति लाने के निर्देश दिए गए। इस दौरान शिक्षा, प्रशानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, राशन भंडारण एवं वितरण सहित अन्य योजनाओं की भी समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। सांसद श्री महाराज ने अधिकारियों को वीबी जी राम जी के व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए ताकि अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो सकें।

## अवैध भण्डारित रेत पर की गई कार्यवाही

बलरामपुर, छ.ग. फ्रंटलाइन। कलेक्टर श्री राजेंद्र कटारा ने जिले में खनिज के अवैध उत्खनन को रोकने के लिए उत्खनन करने वालों पर कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं खनिज विभाग को दिए हैं। इसी बीच शादी-विवाह के मौसम में डीजे और ढोल-नगाड़ों की तेज ध्वनि से छात्रों को पढ़ाई में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसे देखते हुए बिश्रामपुर थाना प्रभारी प्रकाश राठौर ने नगरवासियों से डीजे कम साउंड में बजाने की अपील की है। थाना प्रभारी ने कहा है

## डीजे कम साउंड में बजाने की थाना प्रभारी की अपील

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन बिश्रामपुर। वर्तमान में सीबीएसई, आईसीएसई एवं माध्यमिक शिक्षा मंडल की बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। इसी बीच शादी-विवाह के मौसम में डीजे और ढोल-नगाड़ों की तेज ध्वनि से छात्रों को पढ़ाई में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसे देखते हुए बिश्रामपुर थाना प्रभारी प्रकाश राठौर ने नगरवासियों से डीजे कम साउंड में बजाने की अपील की है। थाना प्रभारी ने कहा है

कि रात 10 बजे के बाद तेज ध्वनि में डीजे बजाना प्रतिबंधित है। उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का हवाला देते हुए स्पष्ट किया कि यदि रात 10 बजे के बाद तेज आवाज में डीजे बजता पाया गया तो डीजे संचालक एवं कार्यक्रम आयोजक के विरुद्ध विधि अनुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि वर्तमान में बोर्ड परीक्षाओं का समय है और तेज ध्वनि छात्रों की पढ़ाई को प्रभावित करती

है, जिसका सीधा असर उनके परीक्षा परिणामों पर पड़ सकता है। इसके अलावा डीजे की अत्यधिक आवाज बीमार व्यक्तियों, बच्चों और बुजुर्गों के स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालती है। थाना प्रभारी ने नागरिकों से अपील की है कि सामाजिक कार्यक्रमों में नियमों का पालन करते हुए ही ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग करें, अन्यथा पुलिस को कार्रवाई के लिए बाध्य होना पड़ेगा।

# प्रधानमंत्री आवास योजना से शिव शंकर का कच्चे मकान से पक्के घर तक का सपना हुआ साकार

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

अम्बिकापुर। शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन से जरूरतमंद परिवारों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के माध्यम से लखनपुर नगर पंचायत के वार्ड क्रमांक 05 में रहने वाले शिव शंकर का वर्षों पुराना पक्का मकान का सपना साकार हुआ है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व तथा मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के हृदय संकल्प से पात्र हितग्राहियों को आवास उपलब्ध कराने का कार्य



प्रार्थमिकता से किया जा रहा है। इसी क्रम में शिव शंकर को योजना अंतर्गत स्वीकृत आवास का लाभ प्राप्त हुआ, जिससे उनका परिवार अब सुरक्षित एवं सम्मानजनक जीवन व्यतीत कर रहा है। शिव शंकर ने बताया कि पहले

उनका परिवार जर्जर कच्चे मकान में रहा करता था। बारिश के दिनों में छत से पानी टपकने के कारण बच्चों सहित पूरे परिवार को गंभीर अस्वविधाओं का सामना करना पड़ता था। सीमित आय और पारिवारिक जिम्मेदारियों के चलते

पक्का मकान बनवाना संभव नहीं हो पा रहा था। ऐसे समय में प्रधानमंत्री आवास योजना उनके लिए आशा की किरण बनकर आई।

## वर्षों पुराना सपना हुआ पूरा

हितग्राही शिव शंकर ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि योजना के सहयोग से उन्हें पक्का घर मिला है, जिससे उनके परिवार को सुरक्षा और स्थायित्व प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि अब वे अपने बच्चों के साथ सुरक्षित वातावरण में सुख-चौन से रह रहे

हैं और उनका वर्षों पुराना सपना पूरा हो गया है।

प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य केवल आवास उपलब्ध कराना ही नहीं, बल्कि आर्थिक रूप से कमजोर जरूरतमंद परिवारों को सम्मानजनक जीवन प्रदान करना है। योजना के प्रभावी क्रियान्वयन से जिले में पात्र लाभार्थियों को पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से सीधे लाभ मिल रहा है। जिला प्रशासन की सतत मॉनिटरिंग और सक्रियता से जिले में आवास निर्माण कार्य प्रगति पर है तथा जरूरतमंद परिवारों को योजनाओं का लाभ सुनिश्चित किया जा रहा है।

# नेशनल लोक अदालत की तैयारी हेतु अधिवक्ताओं संग हुई महत्वपूर्ण बैठक

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन



जरी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन में मार्च में आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत को सफल बनाने के उद्देश्य से जरी न्यायालय परिसर में अधिवक्ताओं की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश तथा अध्यक्ष, तालुका विधिक सेवा समिति ओम प्रकाश सिंह चौहान ने की। बैठक में लोक अदालत के माध्यम से अधिक से अधिक प्रकरणों के निराकरण पर जोर दिया गया। विशेष रूप से बीमा कंपनियों से संबंधित प्रकरणों के शीघ्र निष्पादन के लिए बीमा

अधिवक्ताओं को आवश्यक निर्देश दिए गए। उन्हें कहा गया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में बीमा दावों सहित अन्य सुलहनीय वादों के पक्षकारों को अधिक से अधिक नोटिस तामील कराते हुए समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करें। अध्यक्ष ने कहा कि लोक अदालत आपसी समझौते के माध्यम से त्वरित और किफायती न्याय प्रदान करने का सशक्त माध्यम है। इससे न केवल लंबित मामलों में कमी आती है, बल्कि पक्षकारों को शीघ्र न्याय भी प्राप्त होता है। बैठक में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी एवं व्यवहार न्यायाधीश (वरिष्ठ श्रेणी) सतीश कुमार खाखा सहित बड़ी संख्या में अधिवक्तागण उपस्थित रहे। बैठक का मुख्य उद्देश्य लोक अदालत की प्रक्रिया को प्रभावी बनाने हुए बीमा संबंधी वादों एवं अन्य सुलह योग्य प्रकरणों के त्वरित और समयबद्ध निपटारे को सुनिश्चित करना रहा।

# महापौर ने किया नाली निर्माणकार्य का भूमि पूजन

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

अम्बिकापुर। शहीद भगत सिंह वार्ड में नाली निर्माण कार्य का भूमि पूजन नगर निगम महापौर मंजूषा भगत, युवा पार्षद दीपक यादव वार्ड वासियों के साथ किया गया। मंजूषा भगत ने कहा वार्ड के ऊर्जावान युवा पार्षद दीपक यादव की सक्रियता से लगातार वार्ड के विभिन्न कार्य नाली, सिंसी रोड के निर्माण कार्य को कराया जा रहा है। नगर निगम अम्बिकापुर में अब लगातार विकास कार्य में गति पकड़ ली है। बहोत जल्द शहर वासियों को समस्याओं से निजात मिलेगा, आगे भी लगातार अन्य विकास कार्य होते रहेंगे। पार्षद दीपक यादव ने नाली निर्माण के साथ अन्य विकास कार्य में भी



प्रगति लाने का वार्ड वासियों को विश्वास दिलाया। चुनाव से पहले किये वादों को पूर्ण करेंगे। भट्टी रोड सोसायटी के सामने गली में नाली का निर्माण चालू हो रहा है आगे भी अनेक विकास कार्य लगातार होंगे। वार्ड के जितने भी खराब नालियां जहा जल भराव होता है, कई जगह पे नाली जर्जर हो

गई है उन्हें बनवाया जाएगा। जर्जर सड़क भी जल्द ही बनेंगे। नगर निगम में सुशासन की सरकार है वार्ड का विकास होगा शहर का विकास होगा इस अवसर पर भाजपा वरिष्ठ नेता राम सिंह, मनोज सिन्हा, अभिमन्यु श्रीवास्तव, गोलू यादव राजन, निगम अधिकारी एम वरिष्ठ जन, माताएं उपस्थित रहें।

# रतनपुर में 8 कछुओं की संदिग्ध मौत, शिकार की आशंका

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

बिलासपुर। धार्मिक नगरी रतनपुर स्थित महामाया मंदिर परिसर के कुंड और बूढ़ा महादेव मंदिर परिसर के तालाब में कछुओं की रहस्यमयी मौत से सनसनी फैल गई है। बूढ़ा महादेव मंदिर के पास स्थित तालाब में एक साथ 8 कछुओं के शव पानी में तैरते मिले। इससे पहले महामाया मंदिर कुंड में भी 2 कछुओं की मौत हो चुकी है। बीते छह दिनों में कुल 10 कछुओं की मौत ने वन विभाग की चिंता बढ़ा दी है।

## भारी वस्तु से- पीटकर मारा गया

दो कछुओं की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ चुकी है, जिसमें अंदरूनी चोट के निशान पाए गए



हैं। प्राथमिक जांच में आशंका जताई जा रही है कि कछुओं को लाठी या किसी भारी वस्तु से पीट-पीटकर मारा गया है। मृत कछुओं की उम्र लगभग चार से पांच महीने बताई जा रही है।

## वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज

ग्रामीणों की सूचना पर वन

विभाग की टीम मौके पर पहुंची और शवों को बाहर निकालकर जांच शुरू की। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। विभाग की टीम मंदिर परिसर में लगे सीसीटीवी

कैमरों की फुटेज खंगाल रही है तथा मंदिर प्रबंधन और सुरक्षा कर्मियों से पूछताछ की जा रही है।

## दोषियों के खिलाफ होगी सख्त कानूनी कार्रवाई

वन अधिकारियों के अनुसार कछुए अनुसूची-एक के संरक्षित वन्यजीव हैं, जिनकी हत्या गंभीर अपराध की श्रेणी में आती है। यदि शिकार या सुनियोजित हत्या की पुष्टि होती है तो दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लगातार हो रही इन घटनाओं से क्षेत्र में आक्रोश और चिंता का माहौल है। वन विभाग ने लोगों से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना दें, ताकि संरक्षित वन्यजीवों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

# सरपंच सहित सैकड़ों ग्रामीण भाजपा में शामिल, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के नेतृत्व पर जताया विश्वास

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

कवर्धा। कवर्धा विधानसभा अंतर्गत ग्राम पंचायत बम्हनी के सरपंच सुरेश कौशिक ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ काग्रेस पार्टी का परित्याग कर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। सभी ने उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के नेतृत्व, सुशासन और क्षेत्र में हो रहे ऐतिहासिक विकास कार्यों से प्रभावित होकर भाजपा में प्रवेश किया। भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने वालों में प्रमुख रूप से सुरेश कौशिक (सरपंच), संतोष पटेल, योगेश धुवें, दुर्गेश्वर, लाला राम,



मोहन, रामायण, छिन्नु, हेमराज, दुखुराम, रामकुमार, अश्वनी,

रमेश, मनोहर, राम औतार, आशकरण, कैलाश सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण एवं युवा शामिल रहे। इस अवसर पर सरपंच सुरेश कौशिक ने कहा कि १२५५ मुख्यमंत्री विजय शर्मा के नेतृत्व में क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास कार्य हो रहे हैं। भाजपा सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों और सुशासन से प्रभावित होकर हम सभी ने भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का निर्णय लिया है। हमें विश्वास है कि भाजपा के साथ जुड़कर हम अपने ग्राम और क्षेत्र के विकास में और अधिक योगदान दे सकेगे।

भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने सभी नए सदस्यों का स्वागत करते हुए कहा कि यह भाजपा की जनहितकारी नीतियों, सुशासन और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के प्रति जनता के बढ़ते विश्वास का प्रतीक है। ग्राम बम्हनी में सैकड़ों लोगों का भाजपा में प्रवेश संगठन की बढ़ती ताकत और जनसमर्थन को दर्शाता है। इस अवसर पर उपस्थित जनसमूह ने भाजपा के प्रति अपना समर्थन व्यक्त करते हुए क्षेत्र में विकास की गति को और आगे बढ़ाने का संकल्प लिया।

# प्रधानमंत्री जीवनज्योति बीमा योजना से मिली 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन



भैयाथान। विकासखण्ड भैयाथान के ग्राम पंचायत केवरा में रहने वाले प्रभात देवांगन के निधन के बाद राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन 'बिहान' से जुड़ी राधा देवांगन को उनके पति की मृत्यु के पश्चात प्रधान मंत्री जीवनज्योति बीमा योजना के तहत 2 लाख रुपए का बीमा क्लेम की राशि मिली है। यह राशि नामांकित सदस्य राधा देवांगन को बैंक सेटल बैंक भैयाथान के द्वारा चेक के रूप में विनय गुप्ता जनपद पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी, अग्रणी बैंक एल०डी०एम० आनंद प्रकाश मिंज

सूरजपुर, बी०डी०सी० इन्द्रावती राजवाड़े, दिलीप कुमार एक्का बी०पी०एम० एवं मनोज गुप्ता ब्रांच मैनेजर भैयाथान के द्वारा चेक के रूप में प्रदाय किया गया। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन 'बिहान' योजनागत गठित के श्रद्धा स्वयं सहायता समूह, ग्राम पंचायत केवरा की सदस्य राधा देवांगन के पति का बीमा इन्द्रावती एफएलसीआरपी के

माध्यम से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में अपना पंजीयन बैंक सेटल बैंक भैयाथान, सूरजपुर में कराया था। वे अपने बीमा के प्रीमियम का भुगतान समय पर करती रही। बीमा क्लेम की प्रक्रिया में बैंक एवं एन आर एम टीम के सहयोग से पूरी की गई, जिससे परिवार को समय पर आर्थिक मदद मिल सकी।

# न्यूट्रिशन फ्लो तकनीक को बढ़ावा देने विशेष बैठक आयोजित

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

रायपुर। वन मंत्री केदार कश्यप के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम द्वारा न्यूट्रिशन फ्लो तकनीक के प्रभावी उपयोग और भविष्य की रणनीति तय करने के लिए एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया। बैठक का उद्देश्य नर्सरियों में पौधों के उत्पादन, प्रबंधन और वन रोपण कार्यों में आधुनिक तकनीक अपनाकर गुणवत्ता और उत्पादकता बढ़ाना था। बैठक में विशेषज्ञों ने बताया कि न्यूट्रिशन फ्लो तकनीक के माध्यम से पौधों को संतुलित पोषक तत्व नियंत्रित तरीके से दिए जा सकते हैं। इससे कम पानी में अधिक उत्पादन संभव होता है और संसाधनों का बेहतर उपयोग किया जा सकता है। इस तकनीक से नियंत्रित



वातावरण में स्वस्थ और गुणवत्तापूर्ण पौधे तैयार किए जा सकते हैं। विशेषज्ञों ने इसके तकनीकी पहलुओं, लाभ, व्यवहारिक उपयोग और संभावित चुनौतियों पर विस्तृत जानकारी दी। अधिकारियों ने निर्णय लिया कि वन विकास निगम की नर्सरियों में इस तकनीक को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। इसके लिए स्पष्ट कार्ययोजना और दीर्घकालिक रोडमैप तैयार किया

जाएगा। बैठक में यह भी सहमति बनी कि कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, उनकी तकनीकी क्षमता विकसित की जाएगी और पहले चरण में पायलट प्रोजेक्ट शुरू किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम की यह पहल वन क्षेत्र में नवाचार, सतत विकास और आधुनिक कृषि-वानिकी तकनीकों को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

# महानगर के सुनियोजित विकास की दिशा में बड़ा कदम

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

गोरखपुर। महानगर के समग्र और सुनियोजित विकास की दिशा में आज एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए गोरखपुर विकास प्राधिकरण (जीडीए) द्वारा निर्मित 16 कालोनियों का औपचारिक रूप से गोरखपुर नगर निगम को हस्तांतरण किया गया। इस निर्णय से संबंधित क्षेत्रों में नागरिक सुविधाओं के विस्तार, नियमित रख-रखाव और प्रभावी शहरी प्रबंधन को नई गति मिलने की उम्मीद है। हस्तांतरण कार्यक्रम के दौरान महापौर डॉ. मंगलेश श्रीवास्तव, जीडीए के उपाध्यक्ष आनंद वर्धन, नगर आयुक्त गौरव सिंह सोमरवाल, नगर निगम एवं जीडीए के अधिकारीगण तथा जनप्रतिनिधिगण उपस्थित रहे। सभी ने इस पहल को महानगर के सुव्यवस्थित विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा मील का पत्थर बताया।

अधिकारियों ने बताया कि अब इन 16 कालोनियों में सड़क, नाली, स्ट्रीट लाइट, साफ-सफाई, पेयजल, सीवर व्यवस्था और अन्य मूलभूत नागरिक सुविधाओं का संचालन व रख-रखाव नगर निगम द्वारा किया जाएगा। इससे कार्यों में समन्वय बढ़ेगा और शिकायतों के त्वरित निस्तारण में भी आसानी होगी। स्थानीय निवासियों को एक ही निकाय के माध्यम से सभी शहरी सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकेंगी, जिससे प्रशासनिक प्रक्रिया अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनेगी। महापौर डॉ. मंगलेश श्रीवास्तव ने कहा कि नगर निगम का उद्देश्य शहर को स्वच्छ, सुंदर और व्यवस्थित बनाना है। नई कालोनियों के जुड़ने से जिम्मेदारियां बढ़ी हैं, लेकिन निगम पूरी प्रतिबद्धता के साथ नागरिकों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए तत्पर है।

# राज्यपाल ने छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर किया नमन

रायपुर। राज्यपाल रमन डेका ने आज छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर उन्हें कोटि-कोटि नमन किया। उन्होंने समस्त देशवासियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल ने आज रायपुर के तात्यापारा में शिवाजी की प्रतिमा के समक्ष द्वीप प्रज्वलन और माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। राज्यपाल डेका ने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने सीमित संसाधनों के बावजूद अदम्य साहस, दूरदृष्टि और संगठन क्षमता के बल पर एक सुदृढ़ एवं लोककल्याणकारी राज्य की स्थापना की। उनका प्रशासनिक ढांचा न्याय, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व पर आधारित था। आयोजन समिति द्वारा इस अवसर पर राज्यपाल को मराठा योद्धा सम्मान स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर विधायक पुरंदर मिश्रा, सुनील सोनी एवं आयोजन समिति के सदस्य उपस्थित थे।

# जनपद पंचायत एसडीओ रिश्तव लेते रंगे हाथों गिरफ्तार



छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

बलौदाबाजार। एंटी कर्षण ब्यूरो ने जनपद पंचायत पलारी में बड़ी कार्रवाई करते हुए एसडीओ गोपाल कृष्ण शर्मा को 25 हजार रुपये की रिश्तव लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। इस घटना से पंचायत महकमे में हड़कंप मच गया है। जानकारी के अनुसार, एसडीओ गोपाल कृष्ण शर्मा ने एक उप सरपंच से कथित रूप से 1 लाख रुपये की रिश्तव की मांग की थी। आरोप है कि किसी कार्य को आगे बढ़ाने के एवज में यह राशि मांगी गई थी। उप सरपंच ने इसकी शिकायत एसीबी से की, जिसके बाद टीम ने योजना बनाकर कार्रवाई की। बताया जा रहा है कि, 1 लाख रुपये की मांग के तहत 25 हजार रुपये की पहली किस्त देने के लिए उप सरपंच एसडीओ के कार्यालय पहुंचे थे। जैसे ही उन्होंने राशि मांगी, पहले से तैनात एसीबी की टीम ने मौके पर दबिश देकर एसडीओ को रिश्तव लेते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया। फिलहाल, एसीबी की टीम कार्यालय में दस्तावेजों की जांच कर रही है और आगे की वैधानिक कार्रवाई जारी है। पूरे मामले का विस्तृत खुलासा जल्द किए जाने की बात कही जा रही है।

सम्पादकीय

युवा एआई को नए रूप में अपनाकर दक्षता निखारें

ते जो से बदलती दुनिया में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) अब कोई भविष्य की कल्पना नहीं, बल्कि वर्तमान की ठोस वास्तविकता बन चुकी है। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, मीडिया और प्रशासन हर क्षेत्र में एआई की पैठ बढ़ रही है। ऐसे समय में युवाओं के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह नहीं है कि एआई आर्या या नहीं, बल्कि यह है कि वे इसे किस रूप में अपनाते हैं। यदि युवा एआई को केवल आसान कामों का सहाय मानेंगे, तो उनकी मूल दक्षताएं कमजोर पड़ सकती हैं, लेकिन यदि वे इसे अपनी क्षमता बढ़ाने का उपकरण बनाएंगे, तो यही तकनीक उन्हें नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है। राजधानी नई दिल्ली में आयोजित पांच दिवसीय 'एआई इम्पैक्ट समिट 2026' इस बदलते परिदृश्य का प्रतीक है। समिट का मुख्य आयोजन भारत मंडल में हो रहा है, जहां 70,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में 'एआई इम्पैक्ट एक्सपोज़' लगाया गया है। 300 से अधिक कंपनियां यहां अपने नवाचारों का प्रदर्शन कर रही हैं। लाइव डेमो के माध्यम से यह दिखाया जा रहा है कि एआई किस तरह रोजमर्रा के जीवन को प्रभावित कर सकता है। यह केवल तकनीकी प्रदर्शनों नहीं, बल्कि भविष्य की झलक है। इस समिट में वैश्विक स्तर की बड़ी हस्तियों की मौजूदगी भारत की बढ़ती भूमिका को रेखांकित करती है। फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुएल मैक्रों की भागीदारी इस आयोजन को अंतरराष्ट्रीय महत्व देती है। वहीं, तकनीकी जगत की चर्चित हस्तियां सैम ऑल्टमैन, रणित पिचय, एलेक्जेंडर वांग, डारियो आमोदेई और क्रिस्टियानो आमोन इस बात का संकेत हैं कि एआई अब वैश्विक सहयोग और प्रतिस्पर्धा का केंद्र बन चुका है। भारत की भी उद्योग जगत के दिग्गज जैसे मुकेश अंबानी, एन. चंद्रशेखरन और सलील पारेख की उपस्थिति यह दर्शाती है कि भारतीय उद्योग एआई को भविष्य की रणनीति का अहम हिस्सा मान रहा है। समिट का मुख्य लक्ष्य कृषि, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में एआई के प्रभाव को बढ़ाना है। यदि एआई का सही उपयोग हो तो किसान फसल की बेहतर योजना बना सकते हैं, डॉक्टर सटीक निदान कर सकते हैं और छात्र व्यक्तिगत सीखने के अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। यह तकनीक केवल उत्पादकता नहीं बढ़ाती, बल्कि अवसरों के नए द्वार भी खोलती है। आसान कार्यों के लिए यदि हर बार एआई का सहारा लिया जाएगा, तो बुनियादी कौशल कमजोर पड़ सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि युवा एआई को प्रतिस्थापन नहीं, बल्कि सहयोगी के रूप में देखें। तकनीकी दक्षता, आलोचनात्मक सोच, रचनात्मकता और नैतिक समझ ये चार स्तंभ ही युवाओं को भविष्य के लिए तैयार करेंगे। भारत पहले ही डिजिटल क्रांति का नेतृत्व कर चुका है। अब एआई के क्षेत्र में भी वह वैश्विक मंच पर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा रहा है। डॉसिंग रोबोट जैसे आकर्षक प्रदर्शन भले ही मनोरंजन का माध्यम हों, पर इनके पीछे छिपी तकनीक यह संकेत देती है कि एआई आधारित रोबोट आने वाले समय में हमारे घरों, दफ्तरों और उद्योगों का हिस्सा बन सकते हैं। ऐसे में युवाओं के लिए यह समय तैयारी का है, नई तकनीकों को समझने और उन्हें रचनात्मक रूप से अपनाने का है। आज की युवा पीढ़ी के सामने विकल्प साफ है या तो वे एआई के बदलावों से डरकर पीछे रह जाएं, या फिर उसे अपना साथी बनाकर आगे बढ़ें। एआई का दौर आ चुका है, अब तब युवाओं को करना है कि वे इसके दर्शक बनें या निर्माता।

मुद्दा

डॉ. मोनिका शर्मा



शादी के वादे और शोषण के

जाल से सजग रहें महिलाएं

हा ल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने महिलाओं के लिए विवाह पूर्व शारीरिक संबंध बनाने को लेकर सजग रहने का प्रभावी संदेश का दिया। ज्ञात हो कि इस विषय पर सुप्रीम अदालत की रेखांकित करने योग्य टिप्पणियां एक 30 वर्षीय महिला की शिकायत से जुड़े मामले में आई हैं। मैट्रिमोनियल साइट के माध्यम से 2022 में आरोपी से मिली महिला के मुताबिक आरोपी ने पहले से शादीशुदा होने के बावजूद शादी का वादा करके उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। आरोपी ने दिल्ली और फिर दुबई में कई बार उसके साथ संबंध बनाए। इतना ही नहीं, दुबई में उसकी बिना अनुमति के अंतरंग वीडियो भी बना लिए। विरोध करने पर वीडियो को उसे ब्लॉकमेल करने के लिए इस्तेमाल किया और वायरल करने की धमकी भी दी। बाद में 2024 में आरोपी ने पंजाब में किसी दूसरी महिला से शादी कर ली। हालिया बरसों में कभी सहमति तो कभी बहकावे में आकर शारीरिक संबंध बनाने के बाद आरोप-प्रत्यारोप के मामले तेजी से बढ़े हैं। किशोरिया और युवतियां ही नहीं परिपक्व उम्र की महिलाएं जाने-अनजाने शारीरिक शोषण के इस जाल में फंसे रही हैं। यह स्थिति आपराधिक आंकड़े बढ़ाने वाली ही नहीं, संबंधों में भरोसे के भाव को कमजोर करने वाली भी है। ऐसे में सर्वोच्च न्यायालय की हालिया टिप्पणियां हर आयु वर्ग की महिला के लिए अपने सम्मान को संरक्षित करने और सुरक्षित रहने के दिशानिर्देशों के समान हैं।

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने शादी से पहले शारीरिक संबंध बनाने से पहले लोगों को बहुत सावधानी बरतने को कहा है। कोर्ट ने कहा कि 'शायद हम पुराने ख्यालात वाले हैं, लेकिन शादी से पहले लड़का और लड़की कानूनी और सामाजिक रूप से अजनबी ही होते हैं। रिश्ते कितने भी गहरे क्यों न हों, शादी पक्की होने तक शारीरिक सम्बन्धों में जाना समझ से परे है। शादी से पहले किसी पर भी पूरी तरह भरोसा नहीं करना चाहिए। लोगों को बहुत सतर्क रहना चाहिए।' निरसंदेह, न्यायालय की टिप्पणियां महिलाओं को व्यावहारिक और जागरूक रहने का संदेश देने वाली हैं। हालांकि, अब समाज में उदारवादी दृष्टिकोण बढ़ रहा है पर ऐसे संबंधों के परिणाम और उनसे जुड़े शारीरिक-मानसिक शोषण से बचने के लिए स्त्रियों को स्वयं भी सजग होना होगा। आज की महिलाएं घर और बाहर अपनी मौजूदगी दर्ज करवा रही हैं। हर क्षेत्र में अपना योगदान दे रही हैं। ऐसे में कोई भी पढ़ी-लिखी महिला ऐसे संबंधों के मामले में अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकती। कहना गलत नहीं होगा कि शोषण और धोखाधड़ी के ऐसे मामलों में झंसा देने की दलील भी उचित नहीं लगती। कानून ही नहीं, समाज और परिवार भी यह नहीं मानेगा कि शिक्षित-सजग महिला ने बहकावे में आकर संबंध बनाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में भी महिला से पूछा कि 'आखिर दुबई तक इतनी दूर क्यों गई? यह तो आपसी सहमति से हुआ लगता है। ऐसे मामलों में जहां शारीरिक संबंध दोनों की मर्जी से बनाए गए हों, यहाँ बलात्कार का केस चलाना और सजा देना ठीक नहीं लगता।' स्पष्ट है कि इस केस को लेकर न्यायालय का सार्थक संवाद और सवाल सब कुछ विचारणीय है। हमारे देश में अधिकतर कानूनी प्रावधान महिलाओं की सहायता के लिए ही बने हैं, लेकिन इन प्रावधानों का इस्तेमाल महिलाएं अपने ही निर्णय के नकारात्मक परिणाम से बचने के लिए नहीं कर सकतीं। चिंतनीय यह भी है कि तमाम आधुनिकताओं के बावजूद महिलाओं को लेकर लोगों की मानसिकता नहीं बदली है। स्त्रियों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार के आंकड़े समाज के समझ समझे बड़े चिंता बने हुए हैं। बावजूद इसके शादी के वादों-इरादों के नाम पर शारीरिक संबंध बनाने के बाद आरोप लगाने के वाक्यें भी खूब हो रहे हैं। तकलीफदेह यह भी है कि इन मामलों से महिलाओं का ही पक्ष कमजोर होता है। खासकर किसी पढ़ी-लिखी महिला के साथ अगर जोर-जबर्दस्ती नहीं की गई है तो उसे भी इन सबकों की जिम्मेदारी लेनी होगी। वास्तव का यह भाव किसी की बातों के भुलाव में आने से पहले ही होना चाहिए। शिक्षित और सशक्त होने के मायने नहीं हैं कि अपनी सुरक्षा के लिए जागरूक रहा जाए। ऐसे धोखे या झंसे में ना आए जो शोषण का शिकार बनाने का जाल हो। मौजूदा दौर में महिलाओं को अपने विचार और व्यवहार में इतनी समझ और जवाबदेही तो रखनी ही होगी।

(लेखिका स्वतंत्र संचालक हैं, वे उनके अपने विचार हैं।)

शिक्षण संस्थानों में जातीय नफरत की बढ़ती खाई



डॉ. संजय शुक्ला

आज जब पूरी दुनिया में धर्म, जाति, नस्ल और लैंगिक भेदभाव के खिलाफ आवाज उठ रहा है तब भारत की राजनीति इसी पर केंद्रित है। देश के उच्च शिक्षा संस्थानों में इन दिनों जातीय कटुता का जहर घोला जा रहा है जिसमें सीधे तौर पर वोटबैंक की राजनीति है। यह आलम तब है जब टाइम्स हायर एजुकेशन के साल 2026 के रैंकिंग में दुनिया के शीर्षस्थ 100 यूनिवर्सिटीज में भारत का कोई भी यूनिवर्सिटी शामिल नहीं है। हम 'विकसित भारत -2047' का सपना देख रहे हैं जिसका सारा दारोमदार हमारे उच्च शिक्षा संस्थानों पर निर्भर है। विचारणीय है कि उच्च शिक्षा संस्थान ज्ञान और अनुसंधान के केंद्र होते हैं जहां नवाचार और समावेशी विकास की बात होती है लेकिन हमारे शिक्षा संस्थानों में इन दिनों जातीय नफरत के नारे सुनाई पड़ रहे हैं। विडंबना है कि हमारे छात्र और युवा सदियों पुराने जातिवाद के झगड़े में उलझ रहे हैं इन परिस्थितियों में भारत कैसे विकसित होगा?

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 'यूजीसी' के 'इंक्विटी रेगुलेशंस 2026' के समर्थन और विरोध में देश के विश्वविद्यालयों में जातीय वैमनस्यता की खाई लगातार बढ़ती जा रही है। नये नियमों के खिलाफत और समर्थन में हो रहे प्रदर्शनों को विभिन्न राजनीतिक दलों और जातीय संगठनों द्वारा भी खूब हवा दिया जा रहा है। स्वर्ण जातियों के संगठन जहां इसे 'काला कानून' बताते हुए नियमों को वापस लेने के लिए सड़कों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए वहीं दलित, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के संगठन नये नियमों को उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता का अक्सर देने वाला बताकर इसे लागू करने की मांग पर अड़े हुए हैं।

बहरहाल सुप्रीम कोर्ट द्वारा नये रेगुलेशंस पर रोक लगाने और मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च निश्चित करने के बावजूद दोनों वर्गों के संगठनों द्वारा किए जा रहे भड़काऊ प्रदर्शनों से अनेक सवाल पैदा हो रहे हैं। सवाल यह कि सुप्रीम अदालत के नये

नियमों पर रोक के बावजूद इसके पक्ष और विपक्ष में हो रहे प्रदर्शनों को सुप्रीम कोर्ट और सरकार पर बेजा दबाव की कोशिश नहीं माना जाना चाहिए? क्या यह अदालत की अवमानना नहीं है? यदि प्रदर्शनकारियों के मंसूबे यही है तो इस मुद्दे पर हो रहे सभी प्रदर्शनों पर सख्ती आवश्यक है। आखिरकार यह सरकार और सुप्रीम कोर्ट के साथ ही देश के सामाजिक सौहार्द से जुड़ा मसला है। सियासी दलों और जातीय संगठनों से भी सवाल है कि शिक्षा के परिसरों में धर्म और जाति का जहर घोलकर देश को अराजकता के आग में झोंकना कितना उचित है? देश 1990 में मंडल कमीशन रिपोर्ट लागू करने के बाद हुए हिंसा, आगजनी और आत्मदाह के देश को नहीं भूला है। सोशल मीडिया आज आम आदमी के जीवन का अहम हिस्सा बन चुका है जिससे सभी उम्र के लोग जुड़े हुए हैं। विडंबना है कि सोशल मीडिया जातीय नफरत की आग में लगातार गी डाल रहा है। सोशल मीडिया पर गौर करें तो इस मुद्दे पर यूजर्स के बीच लगातार टकराव बढ़ रहा है और लोगों के बीच मर्यादा की सीमा भी टूट रही है। सोशल मीडिया इस मुद्दे पर जिस तरह से आपत्तिजनक कंटेंट को बढ़ावा दे रहा है उससे इस माध्यम के जवाबदेही पर भी सवालिया निशान लग रहा है। इस बीच अहम सवाल यह भी कि विश्वविद्यालय कैम्पस में बढ़ रहे इस जातीय तनाव पर सरकार और प्रशासन क्यों चुपची साधे हुए हैं?

गौरतलब है कि देश के सर्वाधिक प्रतिष्ठित समझे जाने वाले दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी 'जेएनयू' और दिल्ली यूनिवर्सिटी 'डीयू' इन प्रदर्शनों के केंद्र बने हुए हैं। इन संस्थानों में हो रहे प्रदर्शनों में राजनीतिक दलों के छात्र संगठनों की प्रमुख भूमिका है जिसके पीछे जातीय संगठनों की सहभागिता है। वामपंथी फ्रंट से जुड़े 'अईसा', 'एसएफआई', 'डीएसएफ', 'एआईएसएफ', समाजवादी, दलित, आदिवासी, ओबीसी और अंबेडकरवादी छात्र संगठन जहां यूजीसी नियमों को लागू करने पर अड़े हुए हैं वहीं दक्षिणपंथी छात्र संगठन 'एबीवीपी' उपरोक्त प्रदर्शनों के खिलाफ आवाज उठा रहा है। नये नियमों के पक्ष और विपक्ष में हो रहे विरोध प्रदर्शनों के दौरान कैम्पस में छात्रों के गुटों के बीच झड़पों की खबरें भी सामने

आ रही है। इन विश्वविद्यालयों के स्टूडेंट्स यूनियन में वामपंथी छात्र संगठनों 'लेफ्ट यूनियो' का कब्जा है जो यूजीसी नियम के समर्थन में सवर्ण जातियों को अपने निशाने पर ले रहे हैं। इस यूनिवर्सिटी के छात्र केवल कैम्पस में ही नहीं बल्कि दिल्ली के जंतर-मंतर में भी यूजीसी के समर्थन में ब्राम्हण के साथ ही अन्य सवर्ण जातियों के खिलाफ आपत्तिजनक नारेबाजी कर रहे हैं फलस्वरूप छात्रों के गुटों के बीच झड़प और जातीय कटुता बढ़ती जा रही है। बीते दिनों दिल्ली यूनिवर्सिटी में वामपंथी छात्र संगठन 'अईसा' और भौम आर्मी के अगुवाई में हो रहे प्रदर्शन के दौरान सवाल पूछने वाले एक महिला यूपीए के साथ प्रदर्शनकारियों ने बदसलूकी और हाथापाई कर दिया जिसके बाद कैम्पस में तनाव बढ़ गया। 'एबीवीपी' के छात्र इस घटना के बाद महिला सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के समर्थन में सामने आ गए फलस्वरूप दोनों संगठनों के छात्रों के बीच जमकर टकराव हो गया।

जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन द्वारा 9 फरवरी 2026 को द्वारा 2001 के संसद हमले के दोषी अफजल गुरु को फांसी दिए जाने के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान जहां प्रदर्शनकारियों ने कश्मीर की आजादी को लेकर 'भारत तेरे दुकड़े होंगे हजार' जैसे राष्ट्रविरोधी नारे लगाए गए। इस दौरान वामपंथी स्टूडेंट्स और एबीवीपी के छात्रों के बीच टकराव हुआ। बाद में इस मामले पर पुलिस कार्रवाई हुई तथा जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन के अध्यक्ष कहैया कुमार सहित अनेक छात्रों की गिरफ्तारी हुई थी। मोदी सरकार के 'सोए-एनआरसी' बिल के खिलाफ जेएनयू में आंदोलन हुआ था और इसी दौरान 5 मार्च 2020 को कुछ नकाबपोश लोगों द्वारा कैम्पस में घुसकर शिक्षकों और छात्रों पर हमला किया गया। इसी साल 6 जनवरी को कैम्पस में उक्त घटना की छठवीं बरसी पर यहां के स्टूडेंट्स यूनियन ने एक कार्यक्रम रखा था। अलबत्ता यूजीसी के नये रेगुलेशंस को लेकर केवल दिल्ली में ही घमासान नहीं मचा है बल्कि देश के अनेक विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में इस कानून के पक्ष और विपक्ष में छात्र संगठनों के बीच तनाव मची हुई है। उदाहरण के तौर पर उत्तर प्रदेश के बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 'बीएचयू', इलाहाबाद, गोरखपुर यूनिवर्सिटी और

लखनऊ यूनिवर्सिटी में भी यूजीसी कानून के समर्थन में प्रदर्शन के दौरान आपत्तिजनक नारेबाजी और तनाव की खबरें हैं। लखनऊ यूनिवर्सिटी में 'समता संघर्षन मार्च' के दौरान वामपंथी, कांग्रेसी, समाजवादी, दलित और अंबेडकरवादी छात्र संगठनों और पुलिस के बीच झड़प हो गई। 'बीएचयू' में भी यूजीसी कानून के पक्ष और विपक्ष में हो रहे प्रदर्शन के दौरान छात्रों के दो गुटों के बीच टकराव की खबरें हैं। इस विश्वविद्यालय के दीवारों पर भारत और ब्राम्हण विरोधी आपत्तिजनक नारे लिखे गए थे। इसी तरह गोरखपुर यूनिवर्सिटी में भी इस गाइडलाइंस के समर्थन और विरोध में हुए प्रदर्शन के दौरान कैम्पस का माहौल गर्म हो गया है। इस यूनिवर्सिटी के कैम्पस में भी सवर्ण समाज और नरेंद्र मोदी व योगी आदित्यनाथ के खिलाफ नारेबाजी हुई। यूजीसी के नये दिशा-निर्देश को लेकर राजस्थान, बिहार और झारखंड के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में प्रदर्शन की खबरें हैं। अलबत्ता इन प्रदर्शनों पर गौर करें तो यूजीसी के नए इन्क्विटी नियम के खिलाफत करने वालों के निशाने पर केंद्र सरकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग था उन्होंने अपने प्रदर्शन के दौरान कर्मी भी एएससी, एस्टी और ओबीसी वर्ग के खिलाफ कोई भी टिप्पणी नहीं की। इसके इतर सुप्रीम कोर्ट द्वारा नये गाइडलाइंस पर रोक लगाने के बाद वामपंथी छात्र संगठनों के अगुवाई में हो रहे प्रदर्शनों में सीधे तौर पर ब्राम्हण, राजपूत, वैश्य सहित अन्य सवर्ण समाज के बारे में लगातार भड़काऊ और आपत्तिजनक नारेबाजी की जा रही जो अत्यंत चिंताजनक है। अलबत्ता देश के शिक्षण संस्थानों में छात्रों के साथ जातिगत, क्षेत्रवाद और लैंगिक आधार पर भेदभाव की खबरों को पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता है। यूजीसी ने संसदीय समिति को सौंपे अपने रिपोर्ट में बताया है कि बीते पांच सालों के दौरान उच्च शिक्षा संस्थानों में जाति आधारित भेदभाव में 118 फीसदी वृद्धि हुई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही नया विनियमन जारी किया गया था लेकिन अदालत ने इन नियमों को अस्पष्ट बताया है इसलिए दुरुपयोग की संभावना जताई है। चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में है लिहाजा इस रेगुलेशंस के समर्थन और विरोध में हो रहा प्रदर्शन किसी भी लिहाज से उचित नहीं है। इन परिस्थितियों में सभी वर्ग के छात्रों और छात्र संगठनों से अपेक्षा है कि वे देश के सामाजिक सौहार्द और समरसता के दृष्टिगत कोई भी ऐसा कदम न उठाएं जिससे शिक्षा परिसरों की मर्यादा और शुद्धता पर आंच आए। (लेखक के अपने विचार हैं।)

मन को अच्छी बातों से जोड़ें

नए साल में संकल्प करने की परंपरा है। बहुत-से लोग बहुत प्रकार के संकल्प करते हैं, जैसे- वजन कम करेंगे, मीठा नहीं खाएंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। ऐसे संकल्प करना भी अच्छी बात है, क्योंकि उससे भी आपके मन की शक्ति बढ़ जाती है और मन की कमजोरी दूर हो जाती है। बहुत-से लोग संकल्प तो करते हैं, परंतु उसे पुरा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि मन



माता-पिता और गुरु के ऋणों से कैसे मुक्त हों

वृंदावन के प्रसिद्ध संत प्रेमानंद महाराज किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। उनके दर्शन के लिए लोगों की लाइनें लगी रहती हैं। भक्त महाराज जी का दर्शन करते ही हैं, साथ में उनसे सवाल भी पूछते हैं। ऐसे ही एक भक्त ने प्रेमानंद महाराज जी से सवाल पूछा कि इसी जन्म में माता-पिता और गुरु के ऋण से मुक्त होने के क्या



संकलित दर्शन

बेईमान हो जाता है। जरूरी है कि हम अपने मन पर नियंत्रण करें। उसके गुलाम नहीं बने। यह कठिन जरूर है, लेकिन असंभव नहीं है। इसके लिए जरूरी है इमानदारीपूर्वक निरंतर प्रयास करने की। जैसे पानी के लिए नीचे गिरना आसान और सहज होता है, परंतु अगर उसे ऊपर उठाना हो, तो मोटरपंप की जरूरत पड़ती है। ऐसे ही हमारे मन के लिए नीचे गिरना आसान और सहज है, तो मोटरपंप की जरूरत पड़ती है। मन को ऊंचा उठाना बहुत मुश्किल है। मन के लिए अच्छी बातों से जुड़ना बहुत मुश्किल है, उनको छोड़ देना सहज है। मन को आदतें ऐसी होती हैं कि उन्हीं आदतों में मन को सुविधा महसूस होने लगती है। हमारा मन कुछ आदतों को पाल लेता है और उन्हीं में खुश रहता है। अगर आप अपनी दिनचर्या में साधना को बढ़ाने का संकल्प करते हैं, तो उसको बिना किसी अटकाव के सालभर चलाते रहना बहुत जरूरी है। भूतकाल बीत चुका है, परंतु वर्तमान आपके हाथ में है, इसलिए आनेवाले कल में क्या होगा, यह आपके आज पर निर्भर करता है। अगर आप अपने आज को साधनापूर्ण, शांतिपूर्ण और सुंदर बना लेंगे, तो निश्चित रूप से आपका कल भी वैसा ही होगा।



लूनर न्यू ईयर



चीनी समुदाय के लोग कोलकाता में लूनर न्यू ईयर सेलिब्रेशन में हिस्सा लेते हुए। लूनर न्यू ईयर को कभी-कभी चीनी न्यू ईयर भी कहा जाता है।

संकलित प्रेरणा

उपाय हैं? ताकि सभी ऋण उतरने से और नाम जप के प्रभाव से दोबारा जन्म ना लेना पड़े। चलिए जानते हैं कि प्रेमानंद महाराज जी ने क्या जवाब दिया। महाराज जी कहते हैं कि नाम जप करते हुए जब हमारा भगवत साक्षात्कार हो जाता है। उन्हीं बताया कि एकादशी स्कंध में भागवत में लिखा हुआ है उद्धव की को भगवान उपदेश करते हैं कि जिसको मेरी प्राप्ति हो जाती है, तो वह समस्त ऋणों से मुक्त हो जाता है। भगवान की प्राप्ति होते ही ऋषि ऋण, मातृ-पितृ, देव, गुरु ऋण सभी ऋणों से मुक्त हो जाता है। पर भगवान की प्राप्ति होनी चाहिए। प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि भगवान की प्राप्ति का कल्याण में भाग्यवत और सरल उपाय है- नाम जप। तो नाम का आधार लेकर निरंतर नाम जप करें, तो भगवत प्राप्ति होगी। वो कहते हैं कि निरंतर नाम जप तभी होगा, जब हमारा आधार पवित्र होगा, हमारे आचरण ठीक होंगे। आचरण गलत हो, नाम गलत हो तो नाम घसीटने पर भी नहीं चलता, मन नहीं लगता है।



आज की पार्टी

असंगठित बल को संगठित करने की पहल

हमारे देश में संगठित क्षेत्र में औपचारिक रूप से पंजीकृत वो व्यवसाय आते हैं, जो श्रम कानून का पालन करते हैं, नौकरी की सुरक्षा और सामाजिक लाभ प्रदान करते हैं। जबकि असंगठित क्षेत्र में औपचारिक व्यवसाय शामिल हैं, जिन्हें बहुत कम या कोई दिनियमन नहीं है, अक्सर नौकरी की सुरक्षा, लाभ और कानूनी सुरक्षा का अभाव रहता है। असंगठित श्रमिक समाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 के अंतर्गत घरो में काम करने वाले श्रमिक, स्व-नियोजित श्रमिक या असंगठित क्षेत्र में मजदूरी करने वाले श्रमिक असंगठित क्षेत्र के दायरे में आते हैं। संगठित क्षेत्र के श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए कई अधिनियम लागू किए जा चुके हैं। असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों के आखड़े एकत्रित करने और उनके नि:शुल्क पंजीकरण के लिए प्रयास हुए हैं। -विजय साहू, रायपुर

ऑफ बीट

होता कुछ है, देखते कुछ हैं भ्रम में कुछ प्रजातियां

कई प्रजातियों द्वारा समझा जाने वाला भ्रम दृश्य भ्रम का अध्ययन मस्तिष्क के से काम करता है इसकी दिलचस्प जानकारी प्रदान करता है। दृश्य भ्रम अवधारणात्मक युटियां हैं, जो संभवतः हमें जटिल प्राकृतिक जानकारी को कुशलतापूर्वक संसाधित करने में सक्षम बनाती हैं। एकल भ्रम एक छवि में बिंदुओं के श्रमिक के आधार पर मात्रा की गतत धारणा का कारण बनता है। जो लोग भ्रम का अनुभव करते हैं वे एक साथ गुच्छित होने पर बिंदुओं की संख्या का अधिक अनुमान लगाएंगे और/या बिखरे होने पर बिंदुओं की संख्या को कम आंकेंगे। हम जानते हैं कि एकल भ्रम मनुष्यों, कैपुटिन बंदरों, गंधियों और शैरों द्वारा महसूस किया जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि चिंपैंजी, रीसस बंदर और परेनु कुतों को भ्रम का एहसास नहीं होता है। दिलचस्प बात यह है कि इंसानों में उम्र एकल भ्रम की धारणा को प्रभावित करती है - छोटे बच्चे बड़े की तुलना में कम संवेदनशील होते हैं। मनुष्यों और अन्य प्रजातियों द्वारा मात्राओं की इस गतत धारणा का अनुभव करने का एक संभावित विकासवादी कारण यह है कि यह हमें बड़ी संख्या में वस्तुओं को अधिक कुशलतापूर्वक और तेजी से संसाधित करने और तुलना करने में मदद दे सकता है।



करंट अफेयर

एआई में स्वास्थ्य सेवा कर्मचारियों के बोझ कम करने की क्षमता

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) में स्वास्थ्य सेवा कर्मचारियों के बोझ कम करने और चिकित्सक-रोगी संबंधों को मजबूत करने की क्षमता है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव पुष्प सलीला श्रीवास्तव ने सोमवार को कहा कि भारत मंडल में एआई इम्यूटो शिखर सम्मेलन 2026 के तहत केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रभाव के लिए एआई का विस्तार: सार्वजनिक-न्यायी भागीदारी विषय पर आयोजित उच्चस्तरीय सामूहिक परिचर्चा में श्रीवास्तव ने कहा कि पिछले एक दशक में भारत की स्वास्थ्य प्रणाली राष्ट्रीय स्तर पर अंतर-संचालनीय डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र में विकसित हुई है। एक प्रमुख भागीदार मंत्रालय के रूप में, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय उच्चस्तरीय समूहिक परिचर्चा, प्रमुख पहल की शुरुआत और अपने समाप्ति प्रदर्शनी स्टॉल पर एआई-संचालित स्वास्थ्य सेवा समाधानों के प्रदर्शन के माध्यम से शिखर सम्मेलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। श्रीवास्तव ने कहा कि भारत की स्वास्थ्य प्रणाली पिछले एक दशक में रिकॉर्ड के बुनियादी डिजिटलीकरण और बेहतर डेटा रिपोर्टिंग से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर अंतर-संचालनीय डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण तक विकसित हुई है।



टैंड

एआई का उपयोग

भारतीय युवा पिछली पीढ़ियों से अलग लोच रखते हैं। शिक्षा में एआई और एआई ने शिक्षा परंपरा जुड़े हुए हैं। नए अपने युवाओं से आदान करता है कि वे एआई का उपयोग शिक्षा में, इसे आनातान, श्रेष्ठता बनाने और ऐसे अक्षुण्ण पहल करने के लिए करें जो भारत को एआई क्षेत्र में एक सशक्त शक्ति के रूप में स्थापित करें। - धर्मेन्द्र प्रधान, कैदरीय शिक्षा मंत्री



अस्पतालों की उपेक्षा

भाजपा सरकार ने सपा काल में बने मेडिकल कॉलेज, केसर इंस्टीट्यूट व अन्य अस्पतालों की जानबूझकर अन्दरूनी की है। भाजपाइयों ने सपाके स्वास्थ्य, और आयुष यूनिवर्सिटी तो खोल ली है परंतु जनिहित के आम अस्पतालों की पूरी तरह उपेक्षा की है। - अक्षितेश यादव, सांसद, सपा



नशा मुक्त पंजाब

पंजाब में पिछले एक साल में 2000 किलो से ज्यादा नशा बरामद, बड़े तस्करो जेल में और अर्थ सौंपियों पर बुरुडोजन चला है। आम आदमी पार्टी सरकार के साफ़सट्टे है, पंजाब में नशा तस्करो नहीं बढेगा। नशा मुक्त पंजाब बनाकर ही दम लेगे। -अरविन्द केजरीवाल, पूर्व सीएम, दिल्ली



एआई की दुनिया

एआई की दुनिया ने नए सिईओ का आगमन हो चुका है। हर कोई संगठित रूप से सीईओ है... और कोई भी सीईओ नहीं है। एआई की दुनिया ने शीर्ष-स्तरीय संगठन व्यवस्था सजगत हो चुकी है। - टोशर कूपर, फिलॉसफर





# छत्तीसगढ़ में आदिवासी नेतृत्व गढ़ रहा है विकास के नए सोपान

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

रायपुर। छत्तीसगढ़ की खूबसूरत वादियों में स्थित जशपुर जिला के ग्राम बगिया में 21 फरवरी को जन्म लेने वाले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सज्जनता और सहृदयता की एक मिसाल हैं। दो वर्ष के अपने मुख्यमंत्रित्व काल में छत्तीसगढ़ राज्य में विकास का एक नया आयाम गढ़ने वाले तथा प्रदेश के नागरिकों के दिलों में राज करने वाले मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय आज अपनी लोकप्रियता के शिखर पर विद्यमान हैं। विष्णुदेव साय जनता के बीच के एक ऐसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं जिनकी सदाशयता और दूरगामी योजनाओं से प्रदेश में विकास और प्रगति का राह आसान हुआ है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय आदिवासी पृष्ठभूमि से आते हैं। कैबिनेट बैठक में राज्य में समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले किसानों को 3100 रूपए प्रति क्विंटल के मान से अंतर की

राशि होली पर्व से पहले एकमुश्त भुगतान किए जाने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में 25 लाख 24 हजार 339 किसानों से 141.04 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कृषक उन्नति योजना के तहत धान के मूल्य के अंतर की राशि के रूप में लगभग 10 हजार करोड़ रूपए का भुगतान होली त्यौहार से पहले एकमुश्त किया जाएगा। मुख्यमंत्री स्वयं एक किसान पुत्र हैं वे किसानों की पीड़ा को भलीभांति जानते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कृषक उन्नति योजना के तहत राज्य के किसानों से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी 3100 रूपए प्रति क्विंटल के मान से की की गई है, जो देश में सर्वाधिक है। बीते दो वर्षों में कृषक उन्नति योजना के तहत राज्य के किसानों को धान के मूल्य के अंतर के रूप में 25 हजार करोड़ रूपए से अधिक का

भुगतान किया जा चुका है। इस साल होली से पूर्व किसानों को 10 हजार करोड़ रूपए का भुगतान होने से यह राशि बढ़कर 35 हजार करोड़ रूपए हो जाएगी। किसान हितैशी सरकार के इस निर्णय से बाजार भी गुलजार होगा, जिससे शहरी अर्थव्यवस्था पर सीधा असर दिखाई देगा, ट्रैक्टर आदि की बिक्री में वृद्धि होगी। प्रदेश की नवीन औद्योगिक नीति से राज्य में अब तक 7 लाख 83 हजार करोड़ रूपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं। मुख्यमंत्री ने अपने दो साल के कार्यकाल में छत्तीसगढ़ को पूरे देश में एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेश की जनता के बीच जाकर जनता का न केवल विश्वास जीता है बल्कि उनके हित को ध्यान में रखकर उन्होंने ऐसी योजनाओं का क्रियान्वयन किया है जिससे छत्तीसगढ़ का समग्र विकास सम्भव हो पाया है। यह केवल और केवल विष्णुदेव साय



जैसे एक संवेदनशील, कर्मठ तथा ऊर्जावान मुख्यमंत्री ही सम्भव कर सकते हैं। विष्णु देव की सुशासन में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। वर्ष 2026 को महतारी गौरव वर्ष घोषित किया गया है। राज्य सरकार ने मातृशक्ति का सम्मान करते हुए 70 लाख महिलाओं को महतारी वंदन

योजना के अंतर्गत प्रतिमाह 1000 रूपए की सहायता राशि प्रदान की जा रही है। प्रदेश के 42 हजार 878 महिला स्व-सहायता समूहों को आसान ऋण से अब तक 129.46 करोड़ रूपए का लाभ दिया गया है। प्रधानमंत्री मातृवृद्धा योजना के अंतर्गत 4.81 लाख महिलाओं को 237 करोड़ रूपए की सहायता राशि दी गई है। राज्य की 19 लाख से अधिक महिलाओं को पूरक पोषण आहार सुनिश्चित की गई है। महिला सुरक्षा के लिए सखी वन स्टॉप सेंटर और महिला हेल्पलाइन 181 की स्थापना की गई है। महिलाओं को रोजगार मूलक कार्यों के जरिए स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाने के लिए पंचायत स्तर पर 52.20

करोड़ की लागत से 179 महतारी सदनों का निर्माण कराया जा रहा है। महिला समूहों के उत्पादों की बिक्री हेतु 200 करोड़ की लागत से नवा रायपुर में यूनिटी मॉल का निर्माण कराया जाएगा। मुख्यमंत्री की पहल पर दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के अंतर्गत प्रदेश के 5.62 लाख भूमिहीन कृषि मजदूरों को प्रतिवर्ष 10 हजार रूपए की आर्थिक सहायता दी जा रही है। राज्य सरकार द्वारा आवास और सामाजिक सुरक्षा को ध्यान में रख कर अब तक 26 लाख परिवारों को प्रधानमंत्री आवास स्वीकृति किए गए हैं। स्वच्छ पेयजल सबका अधिकार है। प्रदेश के 41 लाख से अधिक घरों तक स्वच्छ पेयजल पहुंच रहा है। गुणवत्तापूर्ण जलापूर्ति के लिए राज्य में 77 जल परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं। 70 समूह जल प्रदाय योजनाओं से प्रदेश के 3208 गांव लाभान्वित हो रहे हैं। इसके

अलावा राज्य के शत-प्रतिशत गांवों का विद्युतीकरण किया जा रहा है। डबल इंजन की सरकार में रावघाट-जगदलपुर रेल परियोजना के साथ रेल नेटवर्क मैप से बस्तर जुड़ रहा है। जगदलपुर-विशाखापट्टनम और रायपुर-विशाखापट्टनम नई सड़क परियोजनाओं से विकास की नई राहें खुल रही हैं। प्रदेश के 32 नगरीय निकायों में नॉलेज बेसड सोसाइटी हेतु लाइट हाउस निर्माण की पहल की जा रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेश के हर वर्ग के लोगों को साथ लेकर चलने का बड़ा उठाया है। उन्होंने प्रदेश के हर वर्ग की बुनियादी सुविधाओं और जरूरतों को ध्यान में रखते हुए पीएम आवास योजना, कृषक उन्नति योजना, नियद नेल्ला नार, अखरा निर्माण योजना जैसी योजनाओं का शुभारम्भ किया है और जनता के बीच अपनी एक अलग छवि निर्मित की है। मुख्यमंत्री साय

जनता के बीच और हर समुदाय के बीच एक ऐसा पुल बनाना जानते हैं जिससे सभी एक दूसरे से जुड़ सकें और सभी प्रदेश के हित में अपनी-अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह भी कर सकें। उन्होंने अपने जीवन का बहुमूल्य समय प्रदेश की जनता को समर्पित कर यह सिद्ध कर दिया है कि उनका जीवन केवल उनका नहीं है अपितु प्रदेश की जनता की निःस्वार्थ सेवा के लिए समर्पित है। वे सही मायने में एक ऐसे जननेता हैं जो सही के लिए जनता ही सब कुछ हैं। ऐसे सेवाभावी और लोकप्रिय जनसेवक बहुत कम होते हैं जिनके लिए जनता का विकास और जनता का साथ ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का अब तक का कार्यकाल इस बात का प्रमाण है कि यदि नेतृत्व ईमानदार, समर्पित और जनता को आकांक्षाओं से जुड़ा हो तो विकास की राह कठिन नहीं होगी।

## गिधवा टैक में प्रवासी मल्लाड का आगमन, बड़ी क्षेत्र की पहचान

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

रायपुर। छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध पक्षी विहार क्षेत्र गिधवा टैक में इस वर्ष अक्टूबर 2025 में एक खास प्रवासी मेहमान ने दस्तक दी। यह मेहमान है सुंदर और आकर्षक जलपक्षी मल्लाड बतख, जिसने पहली बार यहां अपना आगमन दर्ज कराया। लंबी प्रवासी यात्रा पूरी कर आई यह मल्लाड गिधवा टैक के शांत और स्वच्छ वातावरण में सहज रूप से बस गई। यहां उपलब्ध सुरक्षित आवास, भरपूर जल और प्राकृतिक भोजन ने उसे



रुकने के लिए अनुकूल माहौल दिया। धीरे-धीरे वह अन्य स्थानीय और प्रवासी पक्षियों के साथ घुल-मिल गई और क्षेत्र का हिस्सा बन गई। गिधवा टैक अपनी समृद्ध

जैव-विविधता और पक्षी प्रेमियों के लिए विशेष पहचान रखता है। मल्लाड के आगमन से यह क्षेत्र और भी आकर्षण का केंद्र बन गया है।

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज अपने निवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित नव नियुक्त खनि निरीक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ खनिज संपदा की दृष्टि से देश के सबसे समृद्ध राज्यों में से एक है और खनिज प्रशासन के प्रभावी संचालन में मैदानी अमले की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है।



मुख्यमंत्री साय ने नव चयनित खनि निरीक्षकों को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि युवाओं पर ही देश और प्रदेश का

भविष्य निर्भर करता है। उन्होंने कहा कि खनिज विभाग में नई नियुक्तियों से विभागीय कार्यबल मजबूत होगा तथा खनिज

अन्वेषण और खनन गतिविधियों को और गति मिलेगी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि नव नियुक्त खनि निरीक्षक अपने दायित्वों का समुचित निर्वहन करते हुए खनिज प्रशासन से जुड़े कार्यों के प्रभावी क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ की धरती लौह अयस्क, कोयला, बॉक्साइट, लाइमस्टोन, टिन, डायमंड, गोल्ड और लिथियम सहित विभिन्न खनिज संपदाओं से परिपूर्ण है। खनिज

राज्य के राजस्व का प्रमुख स्रोत भी है और सरकार खनिज राजस्व में वृद्धि के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री साय ने नव नियुक्त अधिकारियों को खनिज राजस्व वृद्धि में सक्रिय योगदान देने के लिए प्रेरित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि खनि निरीक्षक के रूप में आप सभी के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। पारदर्शिता, ईमानदारी और निष्ठा के साथ कार्य करते हुए राज्य के संसाधनों के संरक्षण और सुव्यवस्थित उपयोग में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं।

## ऊर्जा विभाग के सचिव डॉ. रोहित यादव ने पत्रकारों से साझा की विभागीय उपलब्धियां

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

रायपुर। ऊर्जा विभाग के सचिव डॉ. रोहित यादव ने आज नया रायपुर स्थित छत्तीसगढ़ संवाद के ऑडिटोरियम में पत्रकारों के साथ ऊर्जा विभाग की उपलब्धियों और आगामी योजनाओं पर विस्तार से अपने विचार साझा किए। उन्होंने बताया कि प्रदेश में ऊर्जा उत्पादन, पारेषण और वितरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है तथा आने वाले वर्षों के लिए एक व्यापक कार्ययोजना पर तेजी से काम किया जा रहा है। डॉ. यादव ने जानकारी दी कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी, एनटीपीसी तथा निजी उत्पादकों को मिलाकर प्रदेश की कुल स्थापित विद्युत क्षमता 30 हजार 671.7 मेगावाट है। इसमें 28 हजार 824 मेगावाट ताप विद्युत, 220 मेगावाट जल विद्युत तथा सोलर, बायोमास आदि स्रोतों से 2,047 मेगावाट क्षमता शामिल है। ताप विद्युत क्षेत्र में छत्तीसगढ़

स्टेट पावर जनरेशन कंपनी की 2,840 मेगावाट, एनटीपीसी व निजी स्वामित्व के बिजलीघरों की 20 हजार 299 मेगावाट तथा कैप्टिव पावर प्लांट्स की 5 हजार 266 मेगावाट क्षमता है। डॉ. यादव ने कहा कि भारत सरकार का फोकस ताप विद्युत पर निर्भरता कम कर कार्बन उत्सर्जन घटाने पर है। नेट जीरो कार्बन लक्ष्य के तहत वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे देश की 50 प्रतिशत ऊर्जा आवश्यकता नवीकरणीय स्रोतों से पूरी की जा सके। इस दिशा में जल विद्युत एवं पंप स्टोरेज परियोजनाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो ग्रिड संतुलन बनाए रखने में सहायक होंगी। राज्य शासन द्वारा पंप स्टोरेज आधारित जल विद्युत परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए नीति 2023 लागू की गई है। इसके तहत छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी द्वारा 8,300



मेगावाट क्षमता के छह स्थलों का चिन्हांकन किया गया है, जिनमें से पांच के फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार हो चुकी हैं और डीपीआर निर्माणार्थी हैं। निजी क्षेत्र में भी लगभग 5,000 मेगावाट क्षमता की परियोजनाओं पर कार्य जारी है। ऊर्जा सचिव डॉ. यादव ने बताया कि नवीकरणीय ऊर्जा विस्तार के तहत एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड एवं राज्य उत्पादन कंपनी के संयुक्त उपक्रम द्वारा लगभग 2 हजार मेगावाट क्षमता की परियोजनाएं विकसित की जा

रही हैं। इनमें अटल बिहारी ताप विद्युत गृह के जलाशय में 6 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर, कोरबा पूर्व के बंद राखंड बांध पर 32 मेगावाट सौर संयंत्र तथा 500 मेगावाट-ऑवर बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम की स्थापना प्रस्तावित है। ऊर्जा सचिव ने बताया कि प्रदेश को देश की ऊर्जा राजधानी बनाने की दिशा में 32 हजार 100 मेगावाट क्षमता की नई परियोजनाओं हेतु विभिन्न संस्थाओं के साथ एमओयू किए गए हैं। इन परियोजनाओं में 12

हजार 100 मेगावाट ताप विद्युत, 4 हजार 200 मेगावाट न्यूक्लियर, 2 हजार 500 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर तथा 13 हजार 300 मेगावाट पंप स्टोरेज क्षमता शामिल है। इन सभी परियोजनाओं के माध्यम से लगभग 3.4 लाख करोड़ रुपये के निवेश का मार्ग प्रशस्त हुआ है, जिसमें कई प्रमुख संस्थाएं भागीदार हैं। डॉ. यादव ने बताया कि छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी द्वारा कोरबा पश्चिम में 660-660 मेगावाट की दो सुपर क्रिटिकल इकाइयों एवं

मड़वा में 800 मेगावाट की इकाई स्थापित करने की दिशा में कार्य प्रगति पर है। पारेषण क्षेत्र में उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए डॉ. यादव ने कहा कि दिसंबर 2023 से जनवरी 2026 के बीच उपकेन्द्रों की संख्या 132 से बढ़कर 137 हो गई है। ट्रांसफार्मरों की कुल क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है तथा 132 केवी लाइनों में पुराने कंडक्टरों को उच्च क्षमता वाले एचटीएलएस कंडक्टर से बदला जा रहा है। साथ ही 5

हजार 200 किमी ऑप्टिकल फाइबर ग्राउंड वायर का इंस्टॉलेशन पूर्ण कर 131 उपकेन्द्रों को डिजिटल संचार नेटवर्क से जोड़ा गया है। वितरण क्षेत्र में प्रगति पर प्रकाश डालते हुए ऊर्जा सचिव ने बताया कि प्रदेश में उपभोक्ताओं की संख्या 65 लाख से अधिक हो गई है। विगत दो वर्षों में हजारों किमी नई लाइनें, उपकेन्द्र एवं ट्रांसफार्मर स्थापित किए गए हैं। जनहितकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, पीएम कुसुम, डॉ. खूबचंद बघेल किसान विद्युत सहायता योजना एवं बीपीएल उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली जैसी योजनाओं से लाखों परिवार लाभान्वित हो रहे हैं। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विद्युतीकरण हेतु नियद नेल्ला नार योजना के अंतर्गत सैकड़ों गांवों तक बिजली पहुंचाई गई है। क्रेडा की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए ऊर्जा सचिव

ने बताया कि विगत दो वर्षों में 26 हजार 794 सोलर सिंचाई पंप, 7 हजार 833 सोलर पेयजल पंप तथा 1 हजार 709 सोलर हार्डमास्ट स्थापित किए गए हैं। आगामी वर्षों में ऑफग्रीड सोलर प्लांट्स एवं रूफटॉप सौर संयंत्रों के विस्तार की कार्ययोजना पर भी कार्य जारी है। डॉ. यादव ने कहा कि ऊर्जा क्षेत्र में संतुलित मिश्रण, तकनीकी आधुनिकीकरण एवं नवीकरणीय ऊर्जा विस्तार के माध्यम से छत्तीसगढ़ को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर एवं अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इस दौरान पत्रकारों के सवालों के भी विस्तृत उत्तर दिए और विभाग की आगामी 03 वर्षों की कार्य योजना साझा की। इस दौरान सीएसपीडीपीएल के एमडी भीम सिंह कंवर, सीएसपीडीपीएल के एमडी एस के कटवार, सीएसपीडीपीएल के एमडी राजेश कुमार शुक्ला सहित विरिष्ठ विभागीय अधिकारियों मौजूद रहे।

## एआई की दुनिया में राष्ट्रीय मंच पर लहराया छत्तीसगढ़ का परचम

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

रायपुर। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित प्रतिष्ठित एआई इम्पैक्ट समिट में छत्तीसगढ़ के युवाओं ने अपनी प्रतिभा का परचम राष्ट्रीय स्तर पर लहराया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर के प्रतिभाशाली सिबिलिंग अनुराग मानिक और आस्था मानिक को इंडिया एआई इम्पैक्ट बिल्डरथॉन प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त कर प्रदेश को गौरवान्वित करने के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा कि 40,000 से अधिक प्रतिभागियों के बीच तीन कठिन चरणों को सफलतापूर्वक पार करते हुए शीर्ष स्थान हासिल करना उनकी असाधारण प्रतिभा, परिश्रम और नवाचार क्षमता का



प्रमाण है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि यह सफलता छत्तीसगढ़ के युवाओं की क्षमता, आत्मविश्वास और उभरती तकनीकी शक्ति का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि प्रतियोगिता में प्रस्तुत उनका कर्तव्यह्व एआई ऐप विशेष रूप से सराहना का केंद्र रहा। यह एप्लिकेशन एआई जनित आवाज और वास्तविक आवाज में अंतर पहचानकर लोगों को डिजिटल धोखाधड़ी से सुरक्षित

रखने में सहायक होगा। तकनीक को सामाजिक सरोकारों से जोड़ने का यह प्रयास आज के डिजिटल युग में अत्यंत उपयोगी और प्रेरणादायक है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ के युवा अपनी परंपराओं और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संजोते हुए आधुनिक तकनीक और नवाचार के क्षेत्र में भी अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। यह उपलब्धि प्रदेश में शिक्षा, नवाचार और अवसरों के विस्तार की दिशा में हो रहे समग्र विकास का सशक्त प्रमाण है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि राज्य के युवा इसी प्रकार नई ऊंचाइयों प्राप्त करते हुए छत्तीसगढ़ को देश और दुनिया में नई पहचान दिलाएंगे।

## भारत मंडपम में एआई इम्पैक्ट समिट: छत्तीसगढ़ का स्टॉल बना आकर्षण केंद्र

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

रायपुर। भारत मंडपम, नई दिल्ली में आयोजित एआई इम्पैक्ट समिट में छत्तीसगढ़ द्वारा स्थापित स्टॉल देश-विदेश से आए निवेशकों, तकनीकी विशेषज्ञों, उद्योग प्रतिनिधियों और आगंतुकों के लिए प्रमुख आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। छत्तीसगढ़ डिवन बाय इंटेलिजेंस थोम पर आधारित इस स्टॉल में राज्य की उभरती कुत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) क्षमता, अत्याधुनिक डिजिटल अधोसंरचना और निवेश संभावनाओं को प्रभावी ढंग से प्रदर्शित किया जा रहा है। स्टॉल में डिजिटल प्रस्तुति, सूचना पैलट और इंटरैक्टिव माध्यमों के जरिए



छत्तीसगढ़ को उभरते टेक्नोलॉजी हब के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, जिससे निवेशकों में विशेष आकर्षण देखा जा रहा है। स्टॉल में विशेष रूप से नवा रायपुर में स्थापित किए जा रहे देश के पहले एआई डाटा सेंटर पार्क की जानकारी प्रमुखता से दी जा रही है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना में लगभग 1000 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित है तथा इसमें एक

लाख तक ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट (जीपीयू) स्थापित किए जाने की क्षमता विकसित की जाएगी। यह परियोजना देश में एआई आधारित सेवाओं, उच्च क्षमता डाटा प्रोसेसिंग और डिजिटल नवाचार को नई गति प्रदान करते हुए छत्तीसगढ़ को भविष्य की अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में स्थापित करने में सहायक होगी।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस अवसर पर कहा कि एआई इम्पैक्ट समिट में छत्तीसगढ़ का स्टॉल देश-विदेश के निवेशकों और तकनीकी विशेषज्ञों के लिए आकर्षण का केंद्र बनना प्रदेश के लिए गर्व का विषय है। उन्होंने कहा कि नवा रायपुर में देश के पहले एआई डाटा सेंटर पार्क के माध्यम से राज्य को डिजिटल नवाचार, उच्च तकनीकी निवेश और भविष्य की अर्थव्यवस्था का अग्रणी केंद्र बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ा जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पहल प्रदेश के युवाओं के सपनों को नई उड़ान देने, नवाचार और उद्यमिता को नई ऊर्जा प्रदान करने तथा छत्तीसगढ़ के उज्वल भविष्य की

मजबूत आधारशिला तैयार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि हृदय संकल्प और दूरदर्शी नीति के साथ छत्तीसगढ़ को नए भारत की डिजिटल क्रांति के अग्रणी राज्यों में स्थापित किया जाएगा। स्टॉल पर औद्योगिक विकास नीति 2024-30 के अंतर्गत एआई, रोबोटिक्स और उन्नत प्रौद्योगिकी क्षेत्रों के लिए उपलब्ध विशेष प्रोत्साहन, अनुसंधान और निवेश-अनुकूल वातावरण की जानकारी भी निवेशकों को दी जा रही है। राज्य में निर्बाध विद्युत आपूर्ति, विकसित हो रहा नवा रायपुर स्मार्ट सिटी, उत्कृष्ट को-कॉलैबोरेशन और उद्योग-हितैषी नीतियों को प्रमुखता से प्रदर्शित किया गया है।

बिहान से जुड़ी दीदी को दी गई 2 लाख की सहायता राशि

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

सूरजपुर। भैयाथान विकासखण्ड के ग्राम केंवरा निवासी प्रभात देवांगन के निधन के बाद "राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान" से जुड़ी श्रीमती राधा देवांगन को उनके पति की मृत्यु के पश्चात प्रधानमंत्री जीवनज्योति बीमा योजना के तहत 2 लाख रुपये का बीमा क्लेम की राशि मिली।

यह राशि नामांकित सदस्य श्रीमती राधा देवांगन को सेन्ट्रल बैंक भैयाथान, द्वारा चेक के रूप में जनपद सीईओ विनय गुप्ता, बैंक एल.डी.एम. आनंद प्रकाश मिंज, सूरजपुर, बी.डी.सी. श्रीमती इन्द्रावती पैकरा, दिलीप कुमार एकाद्री मनोज गुप्ता ब्रांच मैनेजर द्वारा चेक दिया गया। बीमा क्लेम की प्रक्रिया में बैंक एवं एन आर एल एम टीम के सहयोग से पूरी की गई, जिससे परिवार को समय पर आर्थिक मदद मिल सकी।

नवविवाहिता ने घर पर लगाई फांसी, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

सूरजपुर। नगर के महावालों में एक नव विवाहिता का शव फांसी पर झूलते मिला है। परिजनों ने हत्या की आशंका व्यक्त की है। शव बरामद कर पुलिस ने जांच शुरू की है। बताया गया है कि बबिता की 9



माह पहले महंगावा के खेलेश्वर राजवाड़े से शादी हुई थी। आज सुबह घटना के समय घर में कोई नहीं था, मृतिका को अकेला छोड़ सभी लोग काम से गए थे। गुरुवार की सुबह बबिता

घर पर अकेली थी और परिजन सभी लोग काम पर गए हुए थे। तभी बबिता ने साड़ी के सहारे घर में फांसी पर झूल गई। घर के अंदर फंदे से झूलता पाया गया, देखते ही देखते मौके पर भीड़ जमा हो गई और सूचना मिलते ही मायके पक्ष के लोग भी रोते-बिलखते मौके पर पहुंच गए। बेटी की मौत से आहत परिजनों ने ससुराल पक्ष पर हत्या के आरोप लगाए हैं। मौके पर पहुंची पुलिस मार्ग कायम कर जांच में जुटी हुई है।

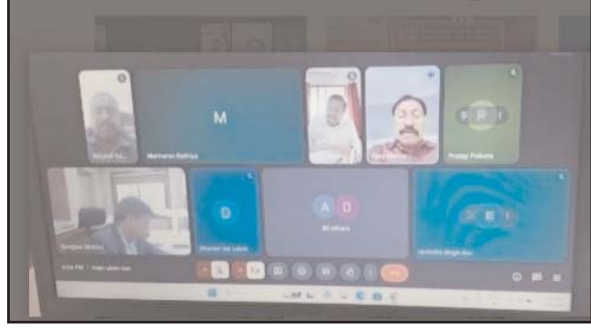
निगरानी सुनिश्चित की जाए। उन्होंने संवेदनशील परीक्षा केंद्रों की विशेष पहचान कर वहीं अतिरिक्त सतर्कता बरतने के केंद्रों पर गोपनीयता बनाए रखना, उड़नदस्ता दल की पूर्ण सक्रियता एवं प्रभावी भ्रमण तथा विद्यार्थियों को तनावमुक्त जिले के 72 केंद्रों में 18.98 हजार परीक्षार्थी देंगे परीक्षा आज से छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित कक्षा 10वीं एवं 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को लेकर जिले में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बताया गया है कि इस वर्ष जिले में कुल 72 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। जिनके माध्यम से बोर्ड की परीक्षाएं संचालित की जाएगी। जिले में इस वर्ष कक्षा 10वीं की परीक्षा में 10,053 परीक्षार्थी शामिल होंगे। जबकि कक्षा 12वीं की परीक्षा में 8,045 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। परीक्षा के सुरुआत एवं सफल संचालन के लिए जिला स्तर पर उड़नदस्ता दल का गठन कर दिया गया है। इसके अलावा परीक्षा से पूर्व सभी विकासखंड शिक्षा अधिकारियों को परीक्षा केंद्रों का भौतिक सत्यापन सुनिश्चित करने हेतु पत्र जारी किया गया है।

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन सूरजपुर। कक्षा 10वीं एवं 12वीं की आगामी बोर्ड परीक्षाओं को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं पारदर्शी रूप से संपन्न कराने के उद्देश्य से कलेक्टर एस. जयवर्धन ने आज शिक्षा विभाग सहित संबंधित अधिकारियों की वरचुअल बैठक ली। बैठक में परीक्षा व्यवस्था की समीक्षा के साथ-साथ नकल प्रकरणों पर प्रभावी रोक लगाने के लिए टोस रणनीति पर चर्चा की गई।

बैठक में संयुक्त कलेक्टर पुष्पेंद्र शर्मा, सर्व एसडीएम, जिला शिक्षा अधिकारी अजय मिश्रा सहित अन्य संबंधित अधिकारी वरचुअल माध्यम से उपस्थित हुए। कलेक्टर श्री जयवर्धन ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी परीक्षा केंद्रों पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था, निरीक्षण दल की तैनाती और सतत

बोर्ड परीक्षाएं विद्यार्थियों के भविष्य की नींव, निष्पक्ष एवं अनुकूल परीक्षा माहौल करें प्रदान : जयवर्धन

कलेक्टर ने ली वरचुअल बैठक, नकल पर सख्ती व संवेदनशील केंद्रों पर विशेष नजर के निर्देश



निर्देश दिए। साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि किसी भी स्तर पर लापरवाही अथवा कोताही पाये जाने पर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। बैठक में परीक्षा व्यवस्था के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की गई, जिसमें प्रश्नपत्रों का सुरक्षित एवं गोपनीय वितरण, परीक्षा

बिहारपुर के चिकित्सक डॉ. शैलेंद्र अग्रहरी का निधन, क्षेत्र में शोक

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

चाँदनी बिहारपुर। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिहारपुर में वर्ष 2010 से पदस्थ चिकित्सक डॉ. शैलेंद्र अग्रहरी आकस्मिक निधन हो गया। मंगलवार की सुबह उन्हें अचानक मस्तिष्काघात आया और शाम को उन्होंने अंतिम श्वास ली।



डॉ. अग्रहरी पिछले लगभग 16 वर्षों से बिहारपुर जैसे दूरस्थ एवं आदिवासी अंचल में निरंतर अपनी सेवाएं दे रहे थे। सीमित संसाधनों और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बीच उन्होंने हजारों मरीजों को उपचार किया। क्षेत्र के ग्रामीणों के लिए वे केवल डॉक्टर ही नहीं, बल्कि एक संरक्षक और मार्गदर्शक के रूप में जाने जाते थे। उनके निधन की खबर मिलते ही स्वास्थ्य विभाग, स्थानीय जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों तथा आम नागरिकों में शोक की लहर दौड़ गई।

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में शोक का माहौल रहा और लोगों ने भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि इतने वर्षों तक निस्वार्थ सेवा देने वाले चिकित्सक का इस तरह अल्प आयु में अस्मय चले जाना पूरे क्षेत्र के लिए अपूरणीय क्षति है। डॉ. शैलेंद्र अग्रहरी का निधन न केवल स्वास्थ्य विभाग के लिए, बल्कि पूरे चाँदनी बिहारपुर एवं ओडगी क्षेत्र के लिए एक गहरा आघात है।

आवास निर्माण में लापरवाही पर होगी कार्यवाही

सूरजपुर एवं भैयाथान में पीएम आवास योजना की हुई पंचायतवार समीक्षा

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

सूरजपुर। जिले के भैयाथान जनपद सभाकक्ष में गुरुवार को प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत अप्रारंभ एवं अपूर्ण आवासों की पंचायतवार विस्तृत समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में एसडीएम, तहसीलदार एवं जनपद के सीईओ ने प्रगत की जानकारी लेते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश दिए। बैठक में तकनीकी सहायक, ग्राम पंचायतों के सरपंच, सचिव तथा रोजगार सहायकों की उपस्थिति में प्रत्येक पंचायत की स्थिति का अलग-अलग परीक्षण किया गया। इस सम्बन्ध में निर्देशित किया गया

कि जिन हितग्राहियों के मकान अभी तक प्रारंभ नहीं हुए हैं या अधूरे हैं, उन्हें प्राथमिकता से पूर्ण कराया जाए तथा लापरवाही



मिलने पर जिम्मेदारों पर कार्यवाही की जाएगी इसके अलावा सूरजपुर एसडीएम द्वारा भी प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को न्यायालय में बुलाकर समझाइश दी गई। उन्हें निर्धारित समय-सीमा में निर्माण

कार्य पूर्ण करने तथा योजना का लाभ समय पर लेने हेतु प्रेरित किया गया। जिला प्रशासन ने सभी पंचायत प्रतिनिधियों को

निर्देशित किया कि वे हितग्राहियों से सतत संपर्क बनाकर निर्माण कार्य की नियमित निगरानी करें, ताकि पात्र परिवारों को शीघ्र पक्का आवास उपलब्ध कराया जा सके।

आज जिले के दुकानों में मनाया जाएगा 'चावल उत्सव'

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

सूरजपुर। कलेक्टर एस. जयवर्धन के निर्देशानुसार जिले की सभी शासकीय उचित मूल्य दुकानों में आज 20 फरवरी को 'चावल उत्सव' का आयोजन किया जाएगा। प्रशासन द्वारा

हितग्राही उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान शेष राशनकार्डधारियों का ई-केवायसी पूर्ण कराने पर विशेष जोर दिया जाएगा। इसके साथ ही उत्सव में विभागीय योजनाओं की जानकारी आम नागरिकों को दी जाएगी तथा सभी दुकानों में



प्रचार-प्रसार हेतु बैनर लगाए जाएंगे। मृत अथवा पलायन कर चुके राशनकार्ड सदस्यों के नाम विलोपन कर लिए सूची तैयार कर 25 फरवरी तक जनपद पंचायत की राशनकार्ड शाखा में प्रस्तुत करने के

इस संबंध में नोडल अधिकारियों एवं दुकान संचालकों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। वर्तमान में फरवरी एवं मार्च 2025 माह का राशन भंडारण किया जा रहा है। इसी क्रम में आयोजित होने वाले चावल उत्सव में स्थानीय जनप्रतिनिधि, निगरानी समिति के सदस्य तथा

निर्देश भी दिए गए हैं। प्रशासन ने सभी संबंधित अधिकारियों और उचित मूल्य दुकान संचालकों को निर्देशित किया है कि 20 फरवरी को अनिवार्य रूप से चावल उत्सव का आयोजन सुनिश्चित करें, ताकि पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ सुचारु रूप से मिल सके।

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता लोक निर्माण विभाग, नवा रायपुर, अटल नगर ( केन्द्रीय निविदा प्रकोष्ठ ) ई-प्रोक्च्यूरमेंट निविदा सूचना Main Portal: <a href="https:// eproc. cgstate. gov. in">https:// eproc. cgstate. gov. in</a> निम्नलिखित कार्य हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है।			
स.क्र.	सिस्टम निविदा क्रमांक /दिनांक	कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित लागत (लाखों में)
1	185503 प्रथम आमंत्रण 12.02.2026	बिलासा देवी कॅम्प एयरपोर्ट बिलासपुर में रनवे का रिकारपेटिंग का कार्य। जमा मद।	1160.49
2	185500 प्रथम आमंत्रण 12.02.2026	जिला बेमतरा के नवागढ़ में कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय भवन का वाटर सप्लाई, सेप्टेज फिटिंग, सेप्टिक टैंक, दसूब वैल, बाऊण्डीवाल, 'आई' टाईप चौकीदार क्वार्टर पहुंच मार्ग एवं विद्युतीकरण सहित निर्माण कार्य। जमा मद।	274.46
3	185604 प्रथम आमंत्रण 12.02.2026	जिला रायगढ़ के रायगढ़ बायपास मार्ग के गोवर्धनपुर रामपुर मार्ग में केलेो नदी पर उच्चस्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य।	1351.90
4	185523 द्वितीय आमंत्रण 12.02.2026	ग्राम -कलेपाल वि.ख.-दरमा मे पी.वी.टी.जी. विद्यार्थियों के लिए 100 सीटर छात्रावास भवन विद्युतीकरण,सहित भवन निर्माण कार्य, जगमद।	269.59
5	185522 द्वितीय आमंत्रण 13.02.2026	जिला जशपुर के घासीमुण्डा से कोरवाटोली (ग्राम पंचायत कोहपानी) मार्ग लंबाई 3.10 कि.मी. निर्माण कार्य।	365.09
6	185523 द्वितीय आमंत्रण 13.02.2026	जिला राजनंदगांव के (1) राजनंदगांव बायपास सर्विस मार्ग लंबाई 7.85 कि.मी. का मजबूतीकरण कार्य, (2) पीपेनगर से संगम चौक मार्ग लं. 1.58 कि.मी. का डामरकाम, (3) प्यारोवाल स्थल चौक से पुलसीपुर स्थले क्रॉसिंग पहुंच मार्ग लं. 0.85 कि.मी. का निर्माण, (4) हिरियाव कोलेज से चार्डडर स्कूल मार्ग लं. 1.50 कि.मी. का निर्माण, (5) अंबेडकर चौक से मोतीपुर अर्धवृत्तिय पहुंच मार्ग लं. 0.75 कि.मी. का निर्माण एवं, (6) रीवागहन बनहस्दी मार्ग लं. 2.60 कि.मी. का कार्य। समूह निविदा।	680.20
7	185524 द्वितीय आमंत्रण 13.02.2026	जिला मोहला मानपुर अं. चौकी के कान्हे धानापायली सेम्हरबांधा मार्ग धानापायली सेम्हरबांधा नाला पर उच्चस्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य।	298.51
8	185525 द्वितीय आमंत्रण 13.02.2026	बोरिदा से ठेंगागुडी तोरा पहुंच मार्ग लंबाई 3.50 कि.मी.(वास्तविक लंबाई 2.00 कि.मी.) का निर्माण कार्य।	634.25
9	185526 द्वितीय आमंत्रण 13.02.2026	जिला बालोद के सांगली से सनौद मार्ग लंबाई 3.26 कि.मी. का पुल पुलिया सहित निर्माण कार्य।	361.13
10	185495 द्वितीय आमंत्रण 13.02.2026	दाडीपारा से इंदलपुर मेनरोड तक मार्ग लंबाई 1.50 कि.मी. का निर्माण कार्य।	219.25
11	185497 द्वितीय आमंत्रण 13.02.2026	जिला बलरामपुर रामानुजगंज के उचरुवा तिमहान से गुरसिंधु कन्हर नदी देवरथल तक पुल-पुलिया सहित मार्ग लं. 2.30 कि.मी. निर्माण कार्य।	258.47
12	185498 द्वितीय आमंत्रण 13.02.2026	मठली से कन्हरपुर छिन्दमेग मार्ग लंबाई 2.875 कि.मी. का निर्माण कार्य।	261.24
13	185527 द्वितीय आमंत्रण 13.02.2026	बरदुली देवरथल मार्ग लंबाई 2.48 कि.मी. का मजबूतीकरण कार्य।	400.61
14	185528 पंचवा आमंत्रण 13.02.2026	जिला बिलासपुर के तखतपुर-बरेला के मध्य मनिरिया नदी पर उच्चस्तरीय जलमन्गीय पुल एवं पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य।	317.76
15	185536 द्वितीय आमंत्रण 13.02.2026	नेवरबांद से बारगांव मार्ग लंबाई 2.90 कि.मी. का निर्माण कार्य।	389.05
16	185538 द्वितीय आमंत्रण 13.02.2026	लोहसी से खोरसी महानदी मार्ग लंबाई 3.11 कि.मी. का मजबूतीकरण कार्य।	355.60
17	185569 तृतीय आमंत्रण 13.02.2026	जिला सूरजपुर के कृपा जमधरपारा से चौकीदारपारा नवापारा शिरकूलपारा तक मार्ग लंबाई 6.10 कि.मी. का निर्माण कार्य।	582.97
18	185572 तृतीय आमंत्रण 13.02.2026	धिनारा से खुंटकुंडा मार्ग लंबाई 10.00 कि.मी. वास्तविक लंबाई 4.525 कि.मी. पुल पुलिया सहित निर्माण कार्य। जमा मद।	503.37

निविदा डाउनलोड करने की अंतिम तिथि सं.क्र. 14, सं.क्र. 17 से सं.क्र. 18 दिनांक 24.02.2026, सं.क्र. 01 से सं.क्र. 03 दिनांक 06.03.2026 निर्धारित है। एवं अन्य शेष निविदाओं के लिए दिनांक 02.03.2026 निर्धारित है। निविदा में भाग लेने की प्रक्रिया एवं निविदा के संबंध में विस्तृत जानकारी विभाग के उपरोक्त वेबसाईट में देखे जा सकते हैं।

मुख्य अभियन्ता  
केन्द्रीय निविदा प्रकोष्ठ  
कार्यालय प्रमुख अभियन्ता  
लोक निर्माण विभाग, नवा रायपुर अटल नगर

जागरूकता अभियान चलकर पुलिस ने बच्चों को दी नए आपराधिक कानून की जानकारी

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

दत्तिया मोड़। पुलिस अधीक्षक प्रशांत कुमार ठाकुर के निर्देशन में करंजी चौकी प्रभारी संतोष सिंह के द्वारा ग्रीन वैली पब्लिक स्कूल में स्कूली विद्यार्थियों के बीच नए आपराधिक कानून के संबंध में एक विशेष जागरूकता अभियान चलाया गया।

इस दौरान चौकी प्रभारी ने विद्यार्थियों को नए आपराधिक कानून की जानकारी सरल और व्यावहारिक उदाहरण के साथ दी। उन्होंने बताया कि भारतीय नई संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय

साक्ष्य अधिनियम का मूल उद्देश्य केवल अपराधी को



दंडित करना ही नहीं बल्कि पीड़ित को पारदर्शी और प्रभावी न्याय दिलाना है। चौकी प्रभारी

ने विद्यार्थियों से कहा कि कानून

की जानकारी ही जागरूक निडर होकर पुलिस से संपर्क करने की सलाह दी। बरहाल

यह कार्यक्रम केवल जानकारी देने तक सीमित नहीं रहा बल्कि अपराधी घटना की स्थिति में पुलिस और समाज के बीच

विश्वास का सेतु मजबूत करने का माध्यम बना सामुदायिक पुलिसिंग के तहत स्कूलों में पहुंच कर सवाद स्थापित करना इस दिशा में एक सकारात्मक पहल मानी जा रही है। इस दौरान प्राचार्य रंजीत सिंह सहित शिक्षक-शिक्षिकाएं पुलिस स्टफ एवं बड़ी संख्या में छात्र-छात्राओं उपस्थित रहे। कुल मिलाकर करंजी पुलिस की यह पहल बताती है कि बदलते कानून के साथ साथ समाज को जागरूक करना भी उतना ही जरूरी है तभी दंड से आगे बढ़कर न्याय की अवधारणा साकार हो सकेगी।

अटल वयो अभ्युदय योजना मोतियाबिंद के ईलाज हेतु जिले के 10 बुजुर्गों को भेजा गया एम्स, कलेक्टर ने दिखाई हरी झंडी

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

सूरजपुर। बुढ़ापे में धुंधली पड़ती आंखों को फिर से रोशन करने की पहल के तहत जिले के 10 वरिष्ठ नागरिकों को मोतियाबिंद के निःशुल्क उपचार के लिए गुरुवार को रायपुर एम्स भेजा गया। यह सुविधा केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी 'अटल वयो अभ्युदय योजना' के अंतर्गत प्रदान की जा रही है। योजना के तहत जिले के 10 वरिष्ठजनों का चयन किया गया। जिनमें 06 पुरुष एवं 04 महिलाएं शामिल हैं। इन सभी को संयुक्त जिला कार्यालय परिसर से विशेष वाहन के माध्यम से एम्स रायपुर रवाना किया गया, जहाँ उनका मोतियाबिंद का सम्पूर्ण उपचार पूरी तरह निःशुल्क

किया जाएगा। रवानगी से पूर्व कलेक्टर एस. जयवर्धन ने चर्चयित बुजुर्गों से व्यक्तिगत मुलाकात की और बस को हरी



झंडी दिखाकर विधिवत रवाना किया। कलेक्टर ने इस अवसर पर कहा कि शासन की यह योजना जिले के वरिष्ठ नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का सार्थक प्रयास है। इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ विजेंद्र सिंह

पाटले, उप संचालक समाज कल्याण आलोक भवाल सहित अन्य संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। अटल वयो अभ्युदय योजना वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य, सम्मान और स्वावलंबन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संचालित की जा रही है। इस योजना के माध्यम से जिले के बुजुर्गों को स्वास्थ्य सेवाओं का सौधा लाभ मिल रहा है।

# सरगुजा फ्रंटलाइन

संपर्क करें

समाचार, ईशतहार, विज्ञापन  
हेतु संपर्क करें।दैनिक छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन  
गौरव पथ, गुरुद्वारा के पास बाबूपारा  
अम्बिकापुरमो. 7566950555  
9713108088

## गुम मोबाइल वापस पाकर खिले चेहरे, 525 नागरिक हुए लाभार्थित

### सरगुजा पुलिस ने एक करोड़ रुपये के गुम मोबाइलों को बरामद किया

छ.ग.फ्रंटलाइन अम्बिकापुर। डीआईजी एवं एसएसपी सरगुजा के निदेशन में साइबर सेल अम्बिकापुर एवं समस्त थाना, चौकी पुलिस टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए अभियान के तहत 525 नग मोबाइल बरामद करके इनके असली मालिकों को सौंपा है। इनकी कीमत लगभग 01 करोड़ रुपये है। राजमोहनी भवन में आयोजित कार्यक्रम में डीआईजी एवं एसएसपी सरगुजा द्वारा संबंधितों को मोबाइल सुपुर्द किया गया, जिससे इनके चेहरों में खुशियां लौट आई।

बता दें कि सरगुजा पुलिस को जिले के विभिन्न थाना, चौकी में लगातार गुम मोबाइल फोन से संबंधित आवेदन प्राप्त हो रहे थे। इन आवेदनों के त्वरित एवं प्रभावी निराकरण के उद्देश्य से डीआईजी एवं एसएसपी सरगुजा राजेश कुमार अग्रवाल के दिशा-निर्देशन में साइबर सेल अम्बिकापुर एवं समस्त थाना, चौकी पुलिस टीम द्वारा गुमे हुए मोबाइल फोन को खोजकर असल मालिकों को



पुनः वापस पहुंचाने हेतु विशेष अभियान की शुरुआत की गई थी। इसी क्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमोलक सिंह दिल्ली एवं नगर पुलिस अधीक्षक राहुल बंसल के नेतृत्व में साइबर सेल एवं जिले के समस्त थाना, चौकी पुलिस टीम द्वारा सर्विलांस तकनीक की मदद से पिछले 05 महीने में कुल 525 गुम मोबाइल फोन बरामद किए, जिसकी कीमत लगभग 01 करोड़ रुपये है। इसे वास्तविक मोबाइल धारकों को सौंपा गया, इससे पूर्व सरगुजा पुलिस द्वारा अगस्त 2025 में 60 नग गुमे हुए मोबाइल फोन को बरामद करके मोबाइल

धारकों को वापस सौंपा गया था। मोबाइल फोन वापस मिलने पर लोगों के चेहरे खुशी से खिल उठे। अधिकतर मोबाइल फोन भीड़भाड़ वाले इलाकों में खो गए थे, जो बाद में ट्रैक कर वापस मांगवाकर पुनः मोबाइल मालिकों को प्रदान किए गए। मोबाइल वापस पाकर नागरिकों के चेहरे पर खुशी और पुलिस के प्रति विश्वास साफ झलकता नजर आया। पुलिस टीम की तकनीकी दक्षता, समन्वय और सतत प्रयासों की आमजनो द्वारा प्रशंसा की गई। कार्यक्रम के दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमोलक सिंह



दिल्ली, नगर पुलिस अधीक्षक अम्बिकापुर राहुल बंसल, थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक शशिकान्त सिन्हा, थाना प्रभारी मणीपुर उप निरीक्षक सी.पी. तिवारी, उप निरीक्षक अभय तिवारी, साइबर सेल प्रभारी सहायक उप निरीक्षक अजीत मिश्रा, सहायक उप निरीक्षक सुभाष टाकूर, आरक्षक अनुज जायसवाल, अमन पुरी, अशोक यादव, अमित विश्वकर्मा, रमेश राजवाड़े, सत्येंद्र दुबे, रामशंकर यादव, सुशील मिंज सक्रिय रहे।

**शर्ट के सामने पॉकेट में मोबाइल रखने से बचें**  
डीआईजी एवं एसएसपी

### भीड़-भाड़ वाले स्थलों से ज्यादातर मोबाइल हुए गायब

आवेदकों ने थाना, चौकी सहित ऑनलाइन पोर्टल पर अपने मोबाइल फोन खोने की शिकायत दर्ज कराई थी। इनमें से अधिकतर मामले बाजारों, सब्जी मंडियों, चौक-चौराहे, यात्रा के दौरान और मंडियों के आस-पास से सामने आए थे, पुलिस टीम ने तकनीकी संसाधनों और अन्य डिजिटल माध्यमों का उपयोग करते हुए इन मोबाइल फोनों को ट्रैक किया और फिर उनके मालिकों को सौंप दिया है।

### आमजनों से सावधानी बरतने की अपील

सरगुजा पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि वे भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर अपने मोबाइल फोन का विशेष ध्यान रखें। अगर फोन गुम हो जाए तो पुलिस को सूचित कर, रिपोर्ट दर्ज करवाएं, इसके पश्चात भारत सरकार के सीईआईआर पोर्टल पर लॉगिन करके गुम मोबाइल की रिपोर्ट अनिवार्य रूप से दर्ज करें।

### जीवन सुरक्षा के लिए करें यातायात नियमों का पालन

इस अवसर पर सरगुजा पुलिस द्वारा सड़क सुरक्षा एवं यातायात जागरूकता अभियान भी चलाया गया। डीआईजी एवं एसएसपी सरगुजा ने उपस्थित नागरिकों को यातायात नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया और विशेष रूप से दोपहिया वाहन चालकों से हेलमेट पहनने की अपील की। नागरिकों को बताया गया कि यातायात नियमों का पालन न केवल कानूनी दायित्व है, बल्कि यह जीवन सुरक्षा के लिए भी अत्यंत आवश्यक है।

### नए कानून का उद्देश्य 'दंड से न्याय' की ओर जाना

सरगुजा पुलिस द्वारा आयोजित कार्यक्रम में नए अपराधिक कानूनों की प्रदर्शनी लगाकर नागरिकों को नए कानून की अवधारणा से अवगत कराया गया। एक जुलाई 2024 से प्रभावी भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए) पर केंद्रित प्रदर्शनी, औपनिवेशिक कानूनों के स्थान पर आधुनिक, तकनीकी-आधारित और न्याय-उन्मुख कानूनी ढांचे को दर्शाया गया। नए कानूनों में फॉरेंसिक जांच, ई-एफआईआर, महिलाओं/बच्चों के खिलाफ अपराधों पर त्वरित कार्रवाई की जानकारी प्रदान की गई। बताया गया कि नए कानून का उद्देश्य 'दंड से न्याय' की ओर जाना बताया गया।

पुलिस विभाग भी आत्मसंतुष्ट वाले इलाकों में सब्जी बाजारों बरतने कहा, साथ ही वापस होता है। डीआईजी एवं में शर्ट के सामने पॉकेट में एसएसपी सरगुजा ने भीड़-भाड़ मोबाइल रखने पर एहतियात शुभकामनाएं दी।

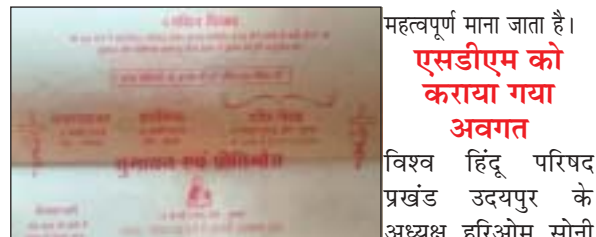
### पीएमएफएमई योजनांतर्गत उद्यमिता जागरूकता शिविर संपन्न

छ.ग.फ्रंटलाइन अम्बिकापुर। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना (पीएमएफएमई) के तहत जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र द्वारा 10 फरवरी को जनपद पंचायत लुण्डा, 11 फरवरी को जनपद पंचायत सीतापुर एवं 12 फरवरी को जनपद पंचायत नर्मदापुर मेनपाट में एक दिवसीय उद्यमिता जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में विभाग द्वारा संचालित प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना (पीएमएफएमई), पी.एम.ई.जी.पी. औद्योगिक विकास नीति 2024-30 की विस्तृत जानकारी उद्यमियों को प्रदान की गई। इस अवसर पर प्रबंधक अश्विनी शुक्ला, सहायक प्रबंधक संदीप पन्ना, संबंधित जनपद पंचायतों के मुख्याधिकारियों, अधिकारी, बीपीएम द्वारा विस्तृत जानकारी प्रदान की गई।

## आदिवासी युवक-युवती का धर्म विशेष के परंपरा अनुसार विवाह की तैयारी सुखियों में

### छ.ग.फ्रंटलाइन उदयपुर।

विकासखंड के ग्राम पंचायत सायर अंतर्गत चौकी केंदमा में रहने वाले एक आदिवासी युवक का धर्म विशेष के रीति-रिवाज अनुसार विवाह की तैयारी इन दिनों सुखियों में है, जबकि वधु पक्ष भी हिंदू समाज से है। दोनों के धर्म विशेष की परम्परा के अनुसार विवाह करने के फैसले से स्थानीय हिंदू समाज में रोष है। समाज के कुछ लोगों का मानना है कि विवाह आदिवासी परंपराओं और हिंदू रीति-रिवाजों के खिलाफ है। धर्म विशेष के परम्परा अनुसार होने वाले विवाह को वे अपनी सांस्कृतिक पहचान पर हमला मान रहे हैं। कुछ लोग इसे धार्मिक मतांतरण या सांस्कृतिक हस्तक्षेप से



जोड़कर देख रहे हैं। अभी तक इस विवाह के संबंध में कोई आधिकारिक शिकायत या कानूनी पहल की सूचना नहीं मिली है। हालांकि, स्थानीय स्तर पर हिंदू समाज के लोगों द्वारा विरोध प्रदर्शन की आशंका जताई जा रही है। मामला सरगुजा जैसे आदिवासी बहुल क्षेत्र में धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक संवेदनशीलता को उजागर करता है। यहां परंपरागत रीति-रिवाजों का पालन बहुत

महत्वपूर्ण माना जाता है।

### एसडीएम को कराया गया अवगत

विश्व हिंदू परिषद प्रखंड उदयपुर के अध्यक्ष हरिओम सोनी ने बताया कि ऐसे दो-तीन मामले आए हैं। एसडीएम वन सिंह नेताम को फोन से अवगत कराया गया है, जांच का आग्रह किया गया है।

### रामचंद्रपुर पुलिस ने कार सवारों से 104 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद किया



छ.ग.फ्रंटलाइन बलरामपुर। जिले के थाना रामचंद्रपुर में पुलिस ने अवैध शराब परिवहन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक लज्जरी कार से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब जब्त कर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लगभग 104 लीटर अंग्रेजी शराब एवं परिवहन में उपयोग किए जा रहे कार को भी जब्त किया है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक 18 फरवरी को मुख्वाब से सूचना मिली कि झारखंड के गढ़वा जिले के थाना चिनिया अंतर्गत ग्राम डोल का अधिमन्यु गुप्ता 30 वर्ष अपने साथी प्रभात कुमार गुप्ता 23 वर्ष के साथ सफेद रंग की टाटा टियागो कार क्रमांक जेएच 03 एबी 3301 में बड़ी मात्रा में अंग्रेजी शराब लेकर गढ़वा मार्ग से होते हुए रामचंद्रपुर की ओर आ रहा है। सूचना पर थाना प्रभारी ने मार्ग पर घेराबंदी करके रखा था। कुछ समय बाद संधिध कार को रोकने का प्रयास किया। इस दौरान चालक व साथी कार छोड़कर भागने लगे। पुलिस ने तत्परात दिखाते हुए दोनों को पकड़ा और कार की तलाशी ली तो 8 पेटों बेंडर एवं 4 पेटों रॉयल ब्रांड की अंग्रेजी शराब मिली, जिसकी कुल मात्रा लगभग 104 लीटर, कीमत करीब 1,46,820 रुपये आंकी गई है। मामले में थाना रामचंद्रपुर में धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर दोनों आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।

## राशन वितरण में लापरवाही पर जिम्मेदारी होंगे संबंधित फुड इंस्पेक्टर

### पीडीएस संचालक 5 किमी से अधिक दूरी वाले ग्रामों में परिवहन, वितरण सुनिश्चित करें

### खाद्य विभाग की बैठक में ई-केवाईसी और धान उठाव में प्रगति लाने के निर्देश

### छ.ग.फ्रंटलाइन अम्बिकापुर।

कलेक्टर अजीत वसंत की अध्यक्षता में गुरुवार को कलेक्टर सभाकक्ष में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले में राशन वितरण व्यवस्था, ई-केवाईसी प्रगति, धान उठाव तथा राशन कार्ड निर्माण की स्थिति की विस्तार से समीक्षा की गई। कलेक्टर ने निर्देशित किया कि राशन भंडारण एवं वितरण व्यवस्था को प्रभावी एवं पारदर्शी बनाया जाए। उन्होंने 19 नवीन उचित-मूल्य राशन दुकानों के चिह्नंकन तथा 5 किलोमीटर से अधिक दूरी



वाले ऐसे 35 ग्रामों में राशन सामग्री के सुचारु परिवहन की व्यवस्था सुनिश्चित कर समय पर वितरण करने के निर्देश दिए। बैठक में कलेक्टर ने जिले के सभी फुड इंस्पेक्टरों को नियमित फिल्टर विजिट कर उचित-मूल्य दुकानों में गुणवत्ता युक्त राशन वितरण व्यवस्था को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि राशन वितरण में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी तथा इसकी पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित

की समीक्षा करते हुए उन्होंने निर्देश दिया कि शत-प्रतिशत ई-केवाईसी कार्य शीघ्र पूर्ण किया जाए तथा इसकी दैनिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। संधिध राशन कार्ड एवं फिल्टर विजिट की साप्ताहिक प्रतिवेदन भी अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने ई-केवाईसी प्रक्रिया की कठोरता-वाइज रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए।

### धान उठाव में तेजी लाने के निर्देश

धान उठाव की जानकारी देते हुए डीएमओ ने बताया कि जिले में लगभग 64 प्रतिशत धान का उठाव हो चुका है, कलेक्टर ने धान उठाव के लिए शत-प्रतिशत डीओ कार्टने के निर्देश दिए, जिससे समय पर धान उठाव हो सके। बैठक जिला खाद्य अधिकारी एसबी कामटे, डीएमओ अरुण विश्वकर्मा, धान अधिकारी जेपी तिवारी सहित संबंधित विभागीय अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।

## सोशल मीडिया में सांप्रदायिक माहौल बनाने के प्रयास का आरोप, कार्रवाई की मांग

### छ.ग.फ्रंटलाइन अम्बिकापुर।

भाजपा युवा मोर्चा सरगुजा केजिलाध्यक्ष ने कोतवाली थाना में आवेदन प्रस्तुत कर सोशल मीडिया के माध्यम से धामक जानकारी प्रसारित कर सांप्रदायिक वैमनस्यता फैलाने तथा लोक व्यवस्था प्रभावित करने के प्रयास की शिकायत दर्ज कराई है। इसमें उल्लेख किया गया है कि 14 से 17 फरवरी 2026 के बीच अकील अहमद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया को लेकर धामक एवं आक्रामक जानकारी प्रसारित की गई, जिससे आमजन में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही है, जबकि मतदाता सूची का पुनरीक्षण निर्वाचन आयोग की नियमित एवं संवैधानिक प्रक्रिया है। शिकायत पत्र में कहा गया है कि अपने सोशल मीडिया अकाउंट एवं अन्य प्लेटफॉर्म के माध्यम से इनके द्वारा यह प्रचारित किया जा रहा है कि मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्यक्रम में प्रशासन द्वारा जानबूझकर मुस्लिम समुदाय के व्यक्तियों का नाम मतदाता सूची से काटने हेतु आपत्तिजनक कार्रवाई की जा रही है। युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष निशांत सिंह ने बताया है कि लगातार इस प्रकार की धामक सूचनाएं प्रसारित कर विभिन्न वर्ग सहित हिंदू-मुस्लिम एवं प्रशासन



के विरुद्ध दुर्भावना उत्पन्न की जा रही है। मतदाता सूची से संशोधन, पुनरीक्षण एक संवैधानिक प्रक्रिया और पारदर्शी प्रक्रिया है जो चुनाव आयोग के अधीन होती है। इसमें

प्रशासन द्वारा किसी भी वर्ग के साथ भेदभाव करने का कोई प्रश्न नहीं उठता। उन्होंने कहा कि अकील अहमद के द्वारा मुस्लिम वर्ग के लोगों का वीडियो बनाकर समाज में असुरक्षा एवं भय का माहौल उत्पन्न किया जा रहा है, जिससे दोनों समुदायों के बीच तनाव की स्थिति उत्पन्न होने की आशंका है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि इनके विरुद्ध धर्म/समुदाय के आधार पर

नफरत फैलाने, सार्वजनिक शांति भंग करने, राष्ट्रीय एकता और अखंडता को क्षति पहुंचाने वाले कृत्य तथा डिजिटल माध्यम से आपत्तिजनक एवं धामक सूचना प्रसारित करने का अपराध दर्ज करते हुए वैधानिक कार्रवाई की जाए। शिकायत दर्ज करने वालों में वीर सोनी, अनुराग शुक्ला, रवजोत सिंह, ऋषभ अम्बोट, सुधांशु चौबे, आयुष दुबे, अविनाश मंडल, रोशन मंडल, ओम सिंह, अतीश पांडेय, शैलेंद्र चौहान, सोनू सहित युवा मोर्चा के कार्यकर्ता-पदाधिकारी उपस्थित थे।

## धान खरीदी को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ले जाने से रजिस्ट्रेशन और भुगतान प्रक्रिया हुई तेज

### पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री ने 259.68 लाख के विकास कार्यों का किया भूमिपूजन

### छ.ग.फ्रंटलाइन अम्बिकापुर।

पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल ने गुरुवार को सरगुजा जिले के लखनपुर विकासखंड अंतर्गत ग्राम केवरा, जमगला, पुष्टपुरा, निम्हा, लहपट्टा, खैरबार, केशवपुर, रामपुर एवं सुखरी के धान उपाजन केंद्रों में विभिन्न विकास कार्यों का विधिवत भूमिपूजन किया। इस अवसर पर उन्होंने क्षेत्रवासियों को बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि राज्य सरकार किसानों की सुविधा और समृद्धि के लिए निरंतर ठोस कदम उठा रही है। इन धान उपाजन केंद्रों में बाउण्ड्री वॉल निर्माण, कवर्ड प्लेटफॉर्म निर्माण तथा अन्य आवश्यक आधारभूत संरचनाओं के विकास कार्य प्रस्तावित हैं। सभी कार्यों का 259.68 लाख रुपये की लागत से निर्माण कराया जाएगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि राज्य सरकार का संकल्प है कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य समय पर मिले और उपाजन प्रक्रिया पूरी तरह सुव्यवस्थित एवं पारदर्शी हो। धान उपाजन केंद्रों में आधारभूत सुविधाओं के सुदृढ़ होने से किसानों की सुरक्षित भंडारण, सुगम परिवहन और व्यवस्थित व्यवस्था का लाभ मिलेगा। इससे उपाजन प्रक्रिया में पारदर्शिता और सुगमता आएगी, जिससे किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बिक्री का पूरा लाभ मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में किसान हित सर्वोपरि है। धान उपाजन व्यवस्था को मजबूत करने के साथ-साथ ग्रामीण अधोसंरचना के विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, ताकि गांवों में ही बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो सकें। उन्होंने आगे कहा कि इन कार्यों के पूर्ण होने से धान खरीदी व्यवस्था और अधिक सुचारु होगी, इससे किसानों को अनावश्यक असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। आधारभूत संरचनाएं मजबूत होने से



ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। राज्य सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाने, किसानों की आय में वृद्धि करने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति देने की दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। धान उपाजन केंद्रों का सुदृढ़ीकरण उसी श्रृंखला की महत्वपूर्ण कड़ी है। राज्य सरकार ने धान खरीदी को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ले जाकर रजिस्ट्रेशन और भुगतान प्रक्रिया को तेज किया है। सरगुजा जैसे आदिवासी बहुल क्षेत्रों में सड़क, भंडारण और बिजली सुविधाओं का विस्तार हो रहा है। मंत्री अग्रवाल ने जोर देकर कहा कि ये विकास कार्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगे और छत्तीसगढ़ को किसान कल्याण का मॉडल राज्य बनाएंगे। पिछले वर्षों में राज्य सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड, बीमा योजनाओं और जैविक खेती प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया है। इन पहलों से किसानों की आय दोगुना करने का लक्ष्य साकार हो रहा है। लखनपुर विकासखंड के इन ग्रामों में होने वाले कार्य पूर्ण होने पर न केवल उपाजन केंद्र आधुनिक बनेंगे, बल्कि स्थानीय रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, कृषकों तथा बड़ी संख्या में ग्रामीणों की उपस्थिति रही। किसानों ने राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों की सराहना करते हुए इसे किसान हित में महत्वपूर्ण पहल बताया।